HP/129/SML/2019-2021

RNI Reference No. 1328500

16-28 फरवरी, 2019

द रीव टाइम्स

The RIEV Times

हिमाचल,
वर्ष 1/ अंक 15/ पृष्ठ: 16
मूल्य: ₹ 25/-

www.therievtimes.com

स्वयं पर विश्वास होने के बाद ही ईश्वर पर विश्वास की कसौटी पर खरा उतरा जा सकता है : डॉ॰ एल.सी. शर्मा

आईआईआरडी की एक और बड़ी उपलब्धि

उड़ीसा में अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम बना रही आईआईआरडी

केंद्रीय पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने किया शिलान्यास

बैडमिंटन, टेबल टेनिस समेत अन्य इंडोर खेलों की होंगी सुविधाएं

द रीव टाइम्स (अंजना ठाकुर)

एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान (आईआईआरडी) प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहा है। यही वजह है कि अंतराष्ट्रीय स्तर की कंपनियां भी आईआईआरडी के साथ मिलकर काम कर रही है। आईआईआरडी हिमाचल की पहली ऐसी संस्था है जो राष्ट्रीय स्तर पर सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) प्रोजेक्ट को पूरा करने में अहम योगदान दे रही है। यही वजह है कि यह संस्था अपने कार्यप्रणाली के बूते देश भर में अपनी एक अलग पहचान और विश्वसनीयता बनाने में कामयाब हो रही है। इसका ताजा उदाहरण उड़ीसा में आईआईआरडी और गेल की साझेदारी से बन रहा इंडोर स्टेडियम है। सीएसआर के तहत इस प्रोजेक्ट को आईआईआरडी गेल इंडिया के साथ मिलकर पूरा करेगा। उड़ीसा के बारंगिल में बनने वाले इस स्टेडियम का इसका शिलान्यास हाल ही में केंद्रीय पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया है। इस मौके पर गेल इंडिया और आईआईआरडी के अधिकारी भी मौजूद रहे। शिलान्यास के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज खेल हमारे जीवन का अहम हिस्सा है और देश के विकास के लिए जरूरी है कि हमारे युवा स्वस्थ रहें। युवाओं को स्वस्थ रखने में खेल गतिविधियों का अहम योगदान रहता है। ऐसे में इंडोर स्टेडियम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में काफी उपयोगी साबित होगी। सीएसआर के तहत निर्मित किए जाने वाले इस स्टेडियम के निर्माण के लिए केंद्रीय पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री गेल इंडिया और आईआईआरडी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोई भी संस्था या संस्थान हो सभी का समाज में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए विकास कार्यों में योगदान देना चाहिए।

आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डाक्टर एलसी शर्मा ने बताया कि यह स्टेडियम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसमें खिलाड़ियों के लिए हर तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। डाक्टर शर्मा ने बताया कि इसके साथ ही कर्नाटक के धारवाड़ में भी आईआईआरडी और गेल इंडिया के साथ मिलकर इंडोर स्टेडियम का निर्माण कर रहा है और इसका कार्य प्रगति पर है। उड़ीसा में बन रहे इंडोर स्टेडियम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अत्याधुनिक खेल सुविधाओं के साथ ही पार्किंग और सोलर लाइटिंग सिस्टम भी होगा। साथ ही दिव्यांगों के लिए भी विशेष सुविधाओं का प्रावधान होगा।

ये होंगी खेल सुविधाएं

बलांगिर में बनने वाले खेल स्टेडियम में इंडोर खेलों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसमें विशेष तरह का बैडमिंटन कोर्ट और टेनिस कोर्ट खिलाड़ियों की जरूरत के मुताबिक तैयार किया जाएगा। बास्केट बॉल के खिलाड़ी भी आसानी से इस स्टेडियम में अपनी प्रतिभा में निखार ला सकेंगे।

खिलाड़ियों के लिए खास तौर पर चेंजिग रूम की भी व्यस्था कोर्ट के साथ की जाएगी। मैच के दौरान अथवा किसी अन्य कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम आने वाले विशिष्ट और अति विशिष्ट लोगों के लिए बैठने और विश्राम करने के लिए लिए अलग से व्यवस्था हो गई।

सुविधाएं
बैडमिंटन कोर्ट
टेबिल टेनिस कोर्ट
चेंजिंग रुम
स्टोर रुम
कार्यालय
सार्वजनिक शौचालय
दिव्यांगो के लिए विशेष शौचालय
प्रवेश लॉउंज
वीआईपी / आगंतुक विश्राम गृह
वीआईपी / मीडिया के बैठने की व्यवस्था
आकर्षक गैलरी
दोपहिया और चौपहिया वाहनों की पार्किंग
सौर बिजली का प्रावधान
खेल सुविधाएं
बैडमिंटन
टेबल टेनिस
बास्केट बॉल
अन्य इंडोर खेल

4.50 करोड़ की लागत से तैयार होगा भवन

इंडोर स्टेडियम के भवन के निर्माण पर करीब 4.50 करोड़ रू. खर्च होंगे। 21 हजार 433 गर्व फीट पर बनने वाले इस भवन में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस स्टेडियम में वर्षा जल संचयन का विशेष प्रबंध होगा और बिजली के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए विशेष तकनीक का इस्तेमाल होगा। स्टेडियम का निर्माण इस तरह से किया जाएगा जिसमें सामान्य खिलाड़ियों के साथ–साथ दिव्यांगों के आने जाने और खेलने के लिए भी विशेष सुविधाएं मिलेगी। स्टेडियम को आगजनी की घटनाओं से सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक अग्निशमन यंत्रो को स्टेडियम के बाहर और भीतर लगाया जाएगा। इसके अलावा आपदा प्रबंधन के अन्य सभी इंतजाम स्टेडियम के बाहर–भीतर किए जाएंगे। उड़ीसा में यह अपनी तरह का पहला स्टेडियम होगा जिससे आधुनिक खेल सुविधाओं से लैस किया जाएगा। दर्शकों के लिए आकर्षक गैलरी का निर्माण भी किया जाएगा।

स्टेडियम की क्षमता
दर्शक दीर्घा की क्षमता–500
अतिरिक्त क्षमता 300
दोपहिया वाहन पार्किंग क्षमता–100
चौपहिया वाहन पार्किंग क्षमता – 30
वीआईपी पार्किंग–8

800 क्षमता वाली दर्शक दीर्घा

इंडोर स्टेडियम में 800 दर्शक एक साथ बैठकर मैच आदि का आनंद ले सकेंगे। इसमें 500 दर्शकों के लिए अलग से दर्शक दीर्घा का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 300 दर्शकों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था होगी। दर्शक दीर्घा में दर्शकों की सुविधा के लिए सभी सुविधाएं होंगी।

पार्किंग की भी व्यवस्था

इंडोर स्टेडियम में आने वाले खिलाड़ियों, दर्शकों को वाहनों की पार्किंग में परेशानी न हो, इसके लिए स्टेडियम में ही पार्किंग की भी व्यस्था की जाएगी। तय योजना के मुताबिक स्टेडियम में 100 दोपहिया वाहनों और 30 चौपहिया वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। जबकि 8 वीआईपी वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था अलग से होगी।

अन्य विशेषताएं

स्टेडियम के भीतर लगने वाले पोल्स और नेट्स दर्शकों की क्षमता के मुताबिक असानी से इधर–उधर स्थानाँतरित किए जा सकेंगे और दर्शकों की क्षमता को अस्थाई तौर पर 2000 तक बढ़ाया जा सकेगा।

ये होंगी विशेषताएं
कुल क्षेत्र–201561 वर्ग फीट
प्रोजेक्ट साइट– 73893 वर्ग फीट
निर्माण क्षेत्र–21433 वर्ग फीट
कुल लागत– 4.50 करोड़
निर्माण विशेषताएं
प्री फेबरीकेटिड / प्री इंजिनीयरिंग भवन निर्माण
वर्षा जल संचयन
सौर ऊर्जा संयत्र
अग्नि सुरक्षा संयत्र
बैडमिंटन कोर्ट में सिंथेटिक फ्लोर
सैंडविच पैनल

मिशन रीव करेगा आपका भविष्य सुरक्षित

प्रदेश में आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एलआईसी के साथ प्रशिक्षण का शानदार आगाज़

ज़िलावार प्रशिक्षण की झलकियां

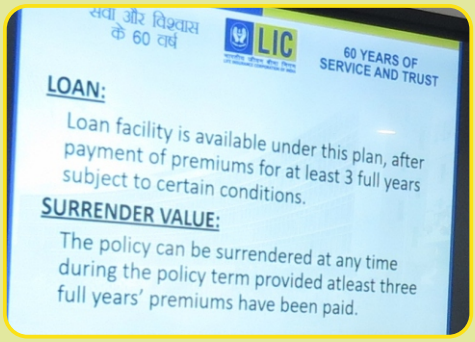

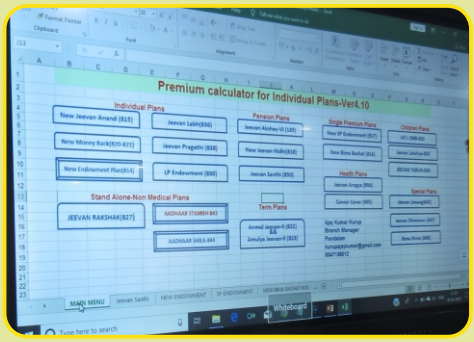

आईआईआरडी के कर्मियों ने मनाया 31 जनवरी का दिन

माह में आए कर्मियों के जन्मदिवस को भी केक काटकर मनाया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को कंपनी के स्टाफ द्वारा एक गेटटुगेदर किया जाता है। 31 जनवरी को भी इस प्रकार का आयोजन कार्यालय सभागार में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य माह भर में कार्यालय की थकान को मनोरंजन और खेल–खेल में मिटाने और कर्मियों के जन्मदिवस को मनाने के लिए किया जाता है। इस माह स्टाफ की लीला और .....का जन्मदिवस था जिसे 31 तारीख को ही सभी ने केक काटकर मनाया।

इसके अलावा यहां दो वर्गों में टीम को बांट कर मनोरंजन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। स्टाफ के कर्मियों ने अपने–अपने विचार भी साझा किए।

इस अवसर पर आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डॉ0 एल सी शर्मा, निदेशक सुषमा शर्मा, मिशन रीव हैड आन्नद नायर, रीव क्लिनिक हैड डॉ0 आर के शांडिल एवं अन्य समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में युवाओं को सुनहरा मौका

युवा दिखा रहे हैं दिलचस्पी, प्रवेश सीमित समय तक

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मिशन रीव सचिवालय शनान में आईआईआरडी काम्पलैक्स में युवाओं के लिए सुनहरा मौका मिल रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत दो ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें जूनियर सॉफ्टवेयर डेवेल्पर और फार्मेसी एसिस्टेंट के लिए प्रार्थी युवाओं से आवेदन मांगे गए हैं।

गौरतलब है कि आईआईआरडी इस प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने की दिशा मे भी प्रयास कर रहा है। प्रशिक्षु को भारत सरकार का प्रमाण पत्र मिलेगा तथा एक बेहतर प्लेसमैंट भी सुनिश्चित करवाई जाएगी। सीमित सीटें होने के कारण युवाओं को इसमें प्रवेश के लिए शीघ्र ही संपर्क करना होगा।

बीमा क्षेत्र में मिशन रीव देगा गांव–गांव में सेवाऐं

एलआईसी और मिशन रीव ने दिया संयुक्त प्रशिक्षण

द रीव टाइम्स ब्यूरो

बीमा के क्षेत्र में मिशन रीव ने बड़ी छलांग लगाने की योजना तैयार कर ली है। इसी के चलते प्रदेश भर में मिशन रीव के सेवाकर्मियों को एलआईसी द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मिशन रीव सचिवालय शनान में भी शिमला ज़िले के रीव सेवाकर्मियों एवं अधिकारियों को बीमा की विस्तार से जानकारी दी गई तथा कौन–कौन से क्षेत्र में प्रारंभिक रुप से बीमा की जानी है, उसकी जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम से आए संजीव शर्मा और करोल ने विस्तार से बताया कि बीमा किसी व्यक्ति को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए कितनी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि दुःख की घड़ी में या आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर पीछे छूट गए परिवार घोर आर्थिक संकट में आ जाते हैं। पूरा परिवार बिखर जाता है।

गांव में आज भी लोग इस सुरक्षा घेरे में नहीं है और अधिकतर ने बीमा नहीं करवाया है। क्योंकि मिशन रीव आज गांव–गांव में लोगों के साथ–लोगों के लिए सेवाऐं दे रहा है.... इसके चलते भारतीय जीवन बीमा निगम ने आईआईआरडी को कॉरोपोरेट एजेंसी के रुप में चुना और अब प्रत्येक परिवार एवं व्यक्ति जो बीमा से वंचित है, उसे मिशन रीव बीमा से जोड़कर आर्थिक सुरक्षा के घेरे में लाएगा। उन्होंने एलआईसी के विभिन्न प्लान पर प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जानकारी दी तथा कहा कि 0 से 100 वर्ष तक के प्रत्येक वर्ग के लिए कोई न कोई सुरक्षित एवं लाभप्रद प्लान एलआईसी के पास उपलब्ध है। इसमें शामिल है जीवन आनंद, स्वास्थ्य आदि।

इस अवसर पर आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डॉ0 एल सी शर्मा ने कहा कि अब आईआईआरडी प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी बीमा क्षेत्र के लिए कॉर्पोरेट ऐजेंसी है। यह प्रदेश की प्रथम कॉर्पोरेट ऐजेंसी है। इसके लिए मिशन रीव के तहत गांव में सभी लोगों की इसकी जानकारी के अलावा बीमा करवाया जाऐगा। उन्होंने एलआईसी को भी विभिन्न ज़िलों में रीव सेवाकर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए योजना बताई।

मिशन रीव हैड आन्नद नायर ने धन्यवाद करते हुए कहा कि आईआईआरडी के तहत मिशन रीव हरसंभव बेहतर परिणाम भविष्य में देगा और आम लोगों को बीमा की सारी योजनाओं की जानकारी देगा और उस दायरे में लाया जाऐगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एल आई सी से मैनेजर सुनील दत्त शर्मा और डिप्टी मैनेजर संजीव करोल, प्रबंध निदेशक आईआईआरडी डॉ0 एल सी शर्मा, निदेशक सुषमा शर्मा, मिशन हैड आन्नद नायर, मुकुल, आईटी हैड राजन मोहंती, रीव क्लिनिक के डॉ0 के आर शांडिल, समाचार पत्र समूह द रीव टाइम्स के संवाददाता और ज़िला शिमला के रीव सेवाकर्मी उपस्थित रहे ।

बीमा क्षेत्र में मिशन रीव देगा गांव–गांव में सेवाऐं

सेवाकर्मियों एवं अधिकारियों को एलआईसी और मिशन रीव ने दिया संयुक्त प्रशिक्षण

विभिन्न क्षेत्रों में होगा बीमा .....हर व्यक्ति का होगा बीमा

बीमा के क्षेत्र में मिशन रीव ने बड़ी छलांग लगाने की योजना तैयार कर ली है। इसी के चलते प्रदेश भर में मिशन रीव के सेवाकर्मियों को एलआईसी द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

रिकांगपियो में जनऔषधी केन्द्र का लोगों को मिलेगा लाभ

दूरदराज के लोग भी जुड़ेगें मिशन रीव की सेवाओं से

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रदेश में प्रधानमंत्री जन औषधी केन्द्रों के खुलने से लोग सस्ती और बहुपयोगी दवाईयों से उपचार के लिए मिशन रीव की सेवाओं को गांव–गांव और दूरदराज के क्षेत्रों में प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश में 300 के लगभग प्रधानमंत्री जन औषधी केन्द्रों को खोलने का लक्ष्य मिशन रीव धीरे–धीरे पूरा करता नज़र आ रहा है। इसी के तहत किन्नौर के दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके, इसी के तहत रिकॉंगपियो में क्षेत्रिय हॉस्पिटल में मिशन रीव द्वारा जनऔषधी केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसके खुलने से दूरदराज के लोगों को लाभ मिलेगा तथा सस्ती दवाईयों के साथ–साथ उपयोगी और आसानी से उपलब्धता को भी मिशन रीव संभव बनाने के लिए प्रयासरत है। द रीव टाइम्स के लिए जारी एक प्रैस विज्ञिप्ति में कहा गया है कि इस प्रकार के जीएमओ प्रदेश में शीघ्र ही खोले जाऐंगे।

मिशन रीव ने प्रधानमंत्री जनऔषधी केन्द्र के उद्घाटन के समय ही अपनी प्रतिबद्धता जताई थी कि प्रदेश के लोगों को सस्ती और उपयोगी दवाईयों की उपलब्धता को मिशन रीव के तहत पहुंचाना संभव बनाया जाऐगा। इसी के परिणामस्वरुप प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में समय–समय पर इन केन्द्रों को खोला जा रहा है। मिशन रीव प्रमुख आन्नद नायर ने बताया कि किन्नौर में प्रधानमंत्री जन औषधी केन्द्र के लिए लोगों की मांग को देखते हुए तथा लोगों को गुणवत्ता आधारित सस्ती दवाईयों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रिय अस्पताल रिकांगपियो में जीएमओ को खोलने की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग ने दे दी है। शीघ्र ही इस सेवा को शुरु करके लोगों को इससे जोड़ा जाएगा तथा मिशन रीव में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि दवाईयों को घर–घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी हो।

IIRD हम जानते हैं गाँव को बेहतर
MISSION RIEV
Ruralising India- Empowering Villages
कि दुनिया देखती रह जाए
भारतीय जन औषधि केन्द्र
दवाईयाँ घर पहुंचाने की व्यवस्था
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र के अन्तर्गत उच्च गुणवत्तापूर्ण दवाईयाँ बेहद कम कीमत पर।
QUALITY ASSURED NABL TESTED WHO GMP cGMP PSU
यहां पर सस्ती दवाईयाँ उपलब्ध है
IIRD Complex, By Pass Road, Shanan, Sanjauli, Shimla-6 HP India
Phone: 0177-2844 073
Website: www.missionriev.in, E mail: info@missionriev.in
फोन पर डाक्टरी परामर्श के लिए सम्पर्क करें.0177-2844 073
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना
800 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाएं व 154 सर्जिकल प्रोडेक्ट्स उपलब्ध
मिशन रीव की अन्य सेवाएं
• स्वास्थ्य सेवाएं
• कृषि/जैविक खेती
• बैंकिंग एवं वित्तिय सेवाएं
• संपत्ति प्रबंधन सेवाएं
• उद्यमिता व्यवसाय प्रबंधन सेवाएं
• ग्रामीण उत्पाद क्रय-विक्रय सेवाएं
• शिक्षा एवं प्रशिक्षण सेवाएं
• यूटिलिटी एवं ऑनलाइन सेवाएं
• रीव जैविक खाद
• पशु आहार (फीड सप्लीमेंट)
• मृदा जांच लैब
• घर पर उपयोग होने वाला सामान
• उपभोक्ता वस्तुएं
• एलईडी टेलिवीज़न

शनान में रीव क्लिनिक में लोग ले रहे हैं स्वास्थ्य सेवाऐं

मरीज़ों को वरदान बना रीव क्लिनिक

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मिशन रीव के तहत शनान, संजौली में खुले रीव क्लिनिक में मरीज़ों की बढ़ती तादात को देखते हुए अत्याधुनिक मशीनों एवं टैस्ट की सुविधाओं को और दुरुस्त किया जा रहा है । रीव क्लिनिक में शनान, चमयाणा, संजौली, भट्टाकुफर, मलयाणा आदि क्षेत्रों से मरीज़ों की संख्या बढ़ रही है । डॉ0 के आर शांडिल ने बताया कि लोग बेहतर इलाज़ और सस्ती दवाईयों का फायदा उठाने के लिए रीव क्लिनिक में आ रहे हैं ।

डॉ0 के आर शांडिल ने बताया कि इस माह आए मरीज़ों में छाती और गले में इंफेक्शन के मरीज़ आए तथा वायरल ने भी लोगों को अपनी चपेट में लिया है । रीव क्लिनिक में लगभग सभी प्रकार के टैस्ट सुविधा है तथा जन औषधी केन्द्र में समस्त प्रकार सस्ती दवाईयों की उपलब्धता भी है ।

बेहतरीन और सस्ती टैस्ट सुविधाओं की लोगों ने तारीफ की है तथा क्षेत्र में इस प्रकार की सुविधाओं के लिए मिशन रीव सराहा है ।

प्रबंध निदेशक आईआईआरडी डॉ0 एल सी शर्मा ने बताया कि मिशन रीव का ध्येय रीव क्लिनिक के माध्यम से ग़रीबों और असहायों के साथ–साथ समाज के सभी वर्गों के लिए सेवाऐं देने का है । इसी के चलते शिमला के अलावा प्रदेश के बाहरी ज़िलों में भी रीव क्लिनिक खोलने की कवायद शुरु की जा रही है । इसे मानव सेवा के ध्येय के साथ आम लोगों तक पहुंचाया जाऐगा ।

सरकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचा रहा मिशन रीव

टीम रीव सिरमौर

ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों को नहीं मिल पाता जिन लोगों के लिए ये योजनाएं बनाई जाती है। ऐसे में न तो सरकार अपने लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त कर पाती है और न ही लोगों को योजनाओं का लाभ मिल पाता है। समाज कल्याण की राह में रोड़ा बन रही इन समस्याओं का निवारण करने में आईआईआरडी का मिशन रीव अहम भूमिका निभा रहा है। दरअसल रीव सरकार और आम जनता के बीच खाई को पाटने में एक मजबूत कड़ी बनता जा रहा है। जिला सिरमौर में मिशन रीव के तहत ऐसे कई उदाहरण है।

सिरमौर के दूर दराज के गांव मिशन रीव लोगों के लिए ग्रामीण विकास का पयार्य बनता जा रहा है। मिशन रीव के तहत उन क्षेत्रों में भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है जहां एक टेस्ट कराने के लिए लोगों को कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। यहां पर मिशन रीव के प्रतिनिधि लोगों को घरों तक सुविधा पहुंचाने में सफल रहे हैं। हिमाचल के आखिरी कोने तक शिलाई के दूरदराज के जौनसार बाबर तक मिशन रीव अपनी पहुंच बनाने में सफल रहा है और इन क्षेत्रों के लोग मिशन रीव की सेवाओं से अपने जीवन का आसान बना रहे हैं।

लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य जांच, जीएसटी नंबर, जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण, राशन कार्ड में नाम जोड़ने, कार लेने, बीएसएनएल का क्नेक्शन दिलाने, बाइक, कार और घर का इंशोरेंस करने और उनके व्यवसाय को आगे ले जाने में मिशन रीव काफी मददगार साबित हो रहा है।

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है
हमारी आवाज़

मिशन रीव की जानकारी दी

मिशन रीव संस्करण –2 में मिलेगी बेहतर सेवाएं

टीम रीव, ऊना

ऊना में हाल ही में मिशन रीव के दूसरे संस्करण का आगाज किया गया है। इस संस्करण के तहत कई नई सेवाओं को शामिल किया गया है। लोगों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने और उन्हें मिशन रीव के दूसरे संस्करण की जानकारी देने के लिए मिशन रीव प्रतिनिधियों की ओर से विशेष जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में लोगों को मिशन रीव संस्करण –2 के तहत गांवों में दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं और उन 10 सेवा प्रभागों के बारे में जानकारी दी जा रही है जो विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए मिशन रीव संस्करण–2 में शामिल किए गए हैं। इन सेवा प्रभागों में लोगों की आवश्यकताओं के मुताबिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही लोग स्वंय भी अपनी आवश्यकताओं का आकलन कर सकते हैं और किसी भी सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी सदस्य इन सेवाओं का लाभ लेना चाहता है तो वह मिशन रीव के माध्यम से आसानी से इन सेवाओं का लाभ ले सकता है। इसके अलावा भी अन्य कई बेहतर सेवाओं को दूसरे संस्करण में शामिल किया गया है।

द रीव टाइम्स बना युवाओं की पसंद

आम लोगों के जीवन का भी हिस्सा

टीम रीव, सोलन

द रीव टाइम्स समाचार पत्र सोलन में युवाओं को खूब पसंद आ रहा है। खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह समाचार पत्र पहली पसंद बन चुका है। 15 दिनों की प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सभी घटनाओं का सार और उस पर आधार प्रश्नोत्तरी अभ्यर्थियों के लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे करूणा, कनिका, तनु, सुरेश व अन्य युवाओं का कहना है कि द रीव टाइम्स में सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न और समसामायिक घटनाओं का पूरा सार होता है। इस समाचार पत्र में महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण परीक्षा के मुताबिक दिया जाता है जिसे विद्यार्थी व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में काफी मदद मिलती है। इसके अलावा हर अंक में केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी जाती है। यह भी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी उपयोगी होती है। विद्यार्थी वर्ग के अलावा आम लोगों के लिए भी यह समाचार पत्र उनके जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। लोगों को कहना है कि समाचार पत्र में सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। इससे योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होती है और साथ ही स्वास्थ्य और कानूनी जानकारी से संबंधित पृष्ठ भी काफी महत्वपूर्ण है।

सोलन में जैविक खाद बदल रही लोगों की आर्थिकी

मिशन रीव के तहत सोलन की विभिन्न पंचायतों में जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण मिश न रीव के तहत दिया जा रहा है। इतना ही नहीं अगर कोई जैविक खाद बनाकर उसकी बिक्री करना चाहता है तो आईआईआरडी की ओर से उसे वह खाद खरीद कर मुनाफा कमाने का अवसर भी दिया जा रहा है। सोलन में सौ से अधिक किसानों को जैविक खाद बनाने का निशुल्क प्रशिक्षण मिशन रीव के तहत दिया गया है। लोग मिशन रीव के इस प्रयास से काफी खुश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अभी तक जैविक खाद बनाकर अपने खेतों में इस्तेमाल की। इसके काफी अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अब लोग अपने खेतों के साथ साथ बिक्री के लिए भी जैविक खाद तैयार करने में जुटे हैं। अभी तक सोलन में विभिन्न किसानों की ओर से तैयार जैविक खाद को मिशन रीव के तहत बाजार उपलब्ध कराया जा चुका है। सोलन के किसानों द्वारा तैयार खाद को मिशन रीव के माध्यम से विभिन्न जिलों में भेजा जा रहा है। ये खाद किसानों द्वारा खासतौर पर बाजार में बिक्री के लिए तैयार की गई है।

किसानों का कहना है कि मिशन रीव के प्रतिनिधियों ने गांव के लोगों को इसका निशुल्क प्रशिक्षण देकर बेहतरीन कार्य किया है। इसका सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि लोगों को प्रशिक्षण लेने के लिए शहर नहीं जाना पड़ता और न ही सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

मिशन प्रतिनिधियों को दिया जीवन बीमा पॉलिसी का प्रशिक्षण

टीम रीव सोलन/ऊना

प्रदेश के अन्य जिलों की सोलन और ऊना में भी गांव के लोगों को आईआईआरडी की ओर से बीमा की सुविधा का लाभ पहुंचाया जाएगा। आईआईआरडी की ओर से भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ साझेदारी की गई है। अब आईआईआरडी मिशन रीव के तहत गांव के लोगों को एलआईआसी करने के लिए अधिकृत है। इसकी शुरूआत जिला चंबा से की गई और अब क्रमवार सभी जिलों में यह सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। इसी कड़ी में जिला ऊना और सोलन में मिशन रीव के प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उन्हें बताया गया कि मिशन रीव भारतीय जीवन बीमा निगम के साझेदार के तौर पर लोगों को बीमा पॉलिसी का लाभ पहुंचाने के लिए अधिकृत है। सोलन में मिशन प्रतिनिधि विजय ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम सोलन के मार्केटिंग मैनेजर रमेश गांधी ने मिशन रीव की टीम को बीमा पॉलिसी के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मिशन प्रतिनिधियों को भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। ऊना के जिला समन्वयक मिशन रीव, हनीश ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान एलआईसी अधिकारियों ने हाल ही में एलआईसी की ओर से लॉच की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और साथ ही मेडीकल योजनाओं के बारे में भी बताया।

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जीवन बीमा के बारे में किस तरह बताकर उन्हें इसका महत्व समझाया जाए, इस बारे में भी प्रशिक्षण के दौरान एलआईसी अधिकारियों की ओर से विस्तार से जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मिशन रीव के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

लोगों को दी मिशन रीव की जानकारी

टीम रीव, सिरमौर

सिरमौर के दूरदराज के गांवों में लोगों को मिशन रीव के बारे में जानकारी देने के लिए विशेष अभियान चलाया गया हैं। इसके तहत मिशन के प्रतिनिधि लोगों के घर जाकर उनकी जरूरतों के बारे में पूछ रहे हैं और प्राथमिकता के आधार पर उन जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हाल ही हाल ही में महीपुर पंचायत में एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस सभा के दौरान लोगों की जरूरतों को जानने के साथ ही द रीव टाइम समाचार पत्र भी लोगों को बांटा गया ताकि वह देश –दुनिया में होने वाली घटनाओं के बारे में अपडेट रह सके।

इसके बाद मिशन रीव के तहत गांवों में दी जा रही विभिन्न सेवाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर ब्लॉक कोआर्डिनेटर वेद प्रकाश और सहायक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने बताया कि मिशन रीव लोगों को उनके घर पर ही स्वास्थ्य स्लेट के माध्यम से बेसिक टेस्ट कराने की सुविधा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कोई दवा की जरूरत पड़ती है तो वह भी मिशन रीव के प्रतिनिधि लोगों को दे रहे हैं। स्वास्थ्य के अलावा कृषि, पशुपालन व ग्रामीण विकास से जुड़ी कई योजनाओं पर भी मिशन रीव कार्य कर रहा है।

डायनामाइट शिमला क्लब ने लगातार 6वीं बार जीती क्रिकेट

20 दिन तक चली प्रतियोगिता में 67 टीमों ने लिया भाग

टीम रीव, सिरमौर

नेरवा चौपाल में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में डायनामाइट शिमला क्लब ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए ट्रॉफी पर कब्जा किया है। पिछले आठ सालों से आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में डायनामाइट क्लब ने लगातार 6वीं बार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस ट्रॉफी पर कब्जा किया। डायनामाइट शिमला क्लब के अध्यक्ष वीनू दिवान ने बताया कि 20 दिनों तक आयोजित इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश की 67 टीमों ने भाग लिया। फाइनल में हुए कड़े मुकाबले में डायनामाइट क्लब ने पहले खेलते हुए 70 रन बनाए। लेकिन इस लक्ष्य का पिछा करते हुए महाकाल 11 की टीम महज 65 रन पर ही ढेर हो गई।

विजेता क्लब के अध्यक्ष वीनू दिवान ने बताया कि उनके क्लब की ओर से क्रिकेट में रूची रखने वाले युवाओं को मौका दिया जाता है और उनकी प्रतिभा निखारने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाती है। दिवान ने बताया कि उनके क्लब से कई ऐसे खिलाड़ी भी जुड़े हैं जो रणजी में भी खेलते हैं। इस क्लब में हिमाचल के युवाओं को प्राथमिकता देते हुए उन्हें क्रिकेट में अपना करियर बनाने का मौका दिया जाता है। इसके साथ ही डीए फिटनेस के माध्यम से इन खिलाड़ियों को फिट रहने के भी टिप्स दिए जाते हैं।

मिशन रीव आपके सहयोग को है तैयार

संपत्ति प्रबंधन डिविजन में लोगों को मिलेगी सुविधाएं

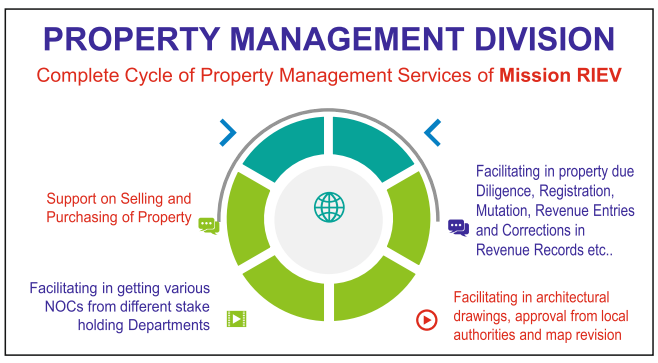

टीम रीव, कांगड़ा

प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह जिला कांगड़ा में भी मिशन रीव के तहत सदस्यों और गैर सदस्यों उन सेवाओं का लाभ मिलेगा जो हाल ही में मिशन रीव संस्करण–2 के तहत शामिल की गई है। मिशन रीव के पहले संस्करण के तहत जब मिशन प्रतिनिधियों की ओर से जिला कांगड़ा के गांवों में विभिन्न लोगों से बात की गई तो उन्होंने अपनी समस्याओं को मिशन रीव के समक्ष रखा। इनमें संपत्ति प्रबंधन को लेकर भी कई समस्याएं सामने आई। इससे देखते हुए मिशन रीव के दूसरे संस्करण में ग्रामीण लोगों की संपत्ति प्रबंधन समस्याओं को दूर करने के लिए संपत्ति प्रबंधन डिविजन को शामिल किया गया है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति की संपत्ति प्रबंधन से जुड़ी समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकेगा। इसके लिए खास तौर पर आवश्यकता आकलन में प्रश्नोत्तरी तैयार की गई। इसी के आधार पर व्यक्ति की आवश्यकता के मुताबिक मिशन रीव उसकी समस्या का हल करेगा।

इन प्रश्नों से होगा आवश्यकता आकलन

1 क्या आपकी जमीन या संपत्ति में टाइटल पेमाइश संबंधी किसी व्यवसाय हेतु सहयोग की आवश्यकता है?

2 क्या आपकी संपत्ति से जुड़े राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार की कोई सुधार की आवश्यकता महसूस होती है?

3 क्या आप अपनी संपत्ति के शेयर को अलग करने अथवा प्लॉट कटवाने हेतु सहयोग की आवश्यकता है?

4 क्या आप जमीन के क्रय विक्रय के लिए हिमाचली कृषक प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं?

5 क्या आप अपने प्लॉट पर घर बनाने का नक्शा बनाने, एनओसी, दस्तातेजी कार्यवाही, नक्शे को संशोधित करने हेतु सहयोग चाहते है?

6 क्या आप कोई सम्पति बेचना / खरीदने में सहयोग चाहते हैं ?

सामाजिक सुरक्षा

1 क्या आप चाहते हैं आपको किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति जैसे की दुर्घटना आदि में यथोचित सहायता मिले ?

2 क्या वृद्धावस्था में चाहते हैं की परिवार वालों की अतिरिक्त और भी कोई आप की देखभाल करे?

3 क्या आपको संपत्ति/ पशु/ या अन्य सामान आदि के बीमा की आवश्यकता महसूस होती है ?

4 क्या आपको शरीर के किसी अंग के प्रत्यारोपण की आवश्यकता महसूस होती है?

5 क्या आप दिव्यांग हैं और आपको किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकया महसूस होती है ?

6 क्या आप बुढ़ापे के लिए कोई पेंशन योजना से जुड़ना चाहेंगे ?

आकलन के आधार पर मिलेगी सेवाएं

अगर संपत्ति प्रबंधन से जुड़ी समस्या का हल किसी भी सदस्य को चाहिए तो उसे इन प्रश्नों को उत्तर देना होगा। सदस्यों के उत्तर के आधार पर आवश्यकता का आकलन होगा और इसी के आधार पर विभिन्न वर्गों में सेवाओं का भी निष्पादन होगा।

विशेषज्ञ सेवाओं के साथ बिक्री के लिए बाजार भी

किसान–बागवानों को सुविधा देगा मिशन रीव

टीम रीव, कांगड़ा

बिलासपुर के विभिन्न जिलों में लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में लोगों को विभिन्न तरह की जानकारी मिशन प्रतिनिधियों की ओर से मुहैया करवाई जा रही है। मिशन रीव के दूसरे संस्करण के तहत किसानों और बागवानों क लिए विशेष तौर पर कृषि डिविजन बनाया गया है। इस सेवा प्रभाग के तहत किसानों और बागवानों को उनकी आवश्कता के मुताबिक सेवाएं प्रदान की जाती है। प्रदेश में अभी भी ऐसे कई किसान है जहां फसलों की पैदावार तो अच्छी होती है लेकिन फसलों को बाजार तक पहुंचाने का सही माध्यम उन्हें नहीं मिल पाता। कई बार ऐसा होता है जब बंपर फसल के बावजूद किसान बागवान अपनी फसलों को बाजार तक नहीं पहुंचा पाते और फसल खेतों में ही बर्बाद हो जाती है। किसानों–बागवानों की इसी समस्या का हल करने के लिए अब मिशन रीव के तहत किसानों–बागवानों को मिशन रीव की ओर से फसलों को बाजार तक पहुंचाने और बेहतर दाम पहुंचाने में सहयोग किया जाएगा।

बिलासपुर के किसान जैविक खाद प्रशिक्षण शिविर लगाने की मांग कर रहे हैं। कुछ किसान जैविक खाद का निर्माण बाजार में बिक्री के लिए भी करना चाहते हैं। ऐसे में किसानों के लिए मिशन रीव के संस्करण–2 के तहत विशेष अभियान चलाने की तैयारी की जा रही हैं। इसमें प्रशिक्षण के अलावा किसानों को विशेष तौर पर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही किसानों को उन योजनाओं का लाभ लेने में मिशन रीव की ओर से विशेष सहयोग दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कृषि विशेषज्ञों को साथ लेकर गांव के किसानों को कृषि के बेहतर तरीकों की भी जानकारी दी जाएगी। किसानों को मृदा जांच की भी सुविधा दी जाएगी। इसके लिए भी विशेषज्ञों की सहायता से किसानों को बताया जाएगा कि जांच के आधार पर वह कैसे अपने खेतों की मृदा का और अधिक उपजाऊ बना सकते हैं तथा मृदा को किस तरह के पोशक तत्वों की अधिक आवश्कता है। कुछ समय पहले ही में मिशन रीव और अन्य विकासात्मक योजनाओं के बारे में लोगों को ग्रामसभा के दौरान जागरूक किया गया। ग्राम सभा के दौरान लोगों को बताया गया कि कैसे मिशन रीव के तहत विभिन्न तरह की सेवाएं गांव में लोगों को दी जा रही है। मिशन रीव के तहत ग्रामीणों के रोजमर्रा की वस्तुओं की आपूर्ति भी घर पर की जा रही है।

गांव में ऑनलाइन हो रहे सभी काम

पैसों के साथ समय की भी बचत

टीम रीव, हमीरपुर

मिशन रीव के तहत गांव के लोगों को ऑनलाइन सुविधा मिल रही है। मिशन रीव गांव में लोगों के घरों पर ही उन्हें यह सुविधा दे रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि पहले बिल जमा कराने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। बाकि के काम रह जाते थे। सिलेंडर बुक कराने और लाने की भी परेशानी रहती थी। लेकिन जब से मिशन रीव क सदस्य बने तब से मिशन रीव के प्रतिनिधि ही हमारे सारे काम कर देते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक पहले छोटे छोटे घरेलु काम जैसे बिजली का बिल जमा करना, बीज खरीदना, गैस सिलेंडर बुक कराना, ये काम खुद की करने पड़ते थे लेकिन अब मिशन रीव ही यह सारे काम कर देता है। रीव प्रतिनिधि जरूरतों के अनुसार सभी काम समय पर पूरा करके देते हैं। इससे परेशानी कम हो गई है और समय की बचत भी हो गई है।

हमीरपुर में सैंकड़ो लोग रीव के तहत सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। मिशन रीव के तहत स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी और पशुपालन से संबंधित विभिन्न तरह के उत्पाद भी लोगों को घरों तक पहुंचाए जा रहे है। इनके लिए पहले लोगों को शहरों की दौड़ लगानी पड़ती थी।

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्थानों पर किसानों को आईआईआरडी की ओर से मिशन रीव के तहत निशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत कलोह, बसोली पंचायत तथा अन्य कई स्थानों प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके अलावा कृषि विभाग की उन सेवाओं के बारे में भी इन किसानों को अवगत कराया जा रहा है जिसका लाभ वे सरकारी तौर पर उठा सकते हैं। इन योजनाओं का लाभ लेने में भी मिशन रीव के सदस्य गांवों के लोगों का भरपूर सहयोग कर रहे हैं ।

बाजार जाने का झंझट खत्म, घर पहुंच रहा ज़रुरत का सामान

टीम रीव, बिलासपुर

मिशन रीव के तहत लोगों को गांवों में ही उनके घर पर वह सामान पहुंचाया जा रहा है जिसके लिए पहले उन्हें कई किलोमीटर का सफर तय करके बाजार जाना पड़ता था। लेकिन अब गांव में उनके अपने घर में ही मिशन रीव के तहत जरूरत का सारा सामान पहुंचाया जा रहा है।

पहले लोगों की जरूरतों को जानने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा लोगों के घरों पर जाकर भी मिशन रीव के प्रतिनिधि आवश्यकता आकलन कर रहे हैं। इसके लिए अलग से आवश्यकता आकलन फॉर्म बनाए गए हैं। इसके माध्यम से लोगों की जरूरतों को जानकर उन्हें मिशन रीव की सेवाएं प्रदान की जा रही है। लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से सामान उनके घर पर ही उपलब्ध करवाया गया। स्वास्थ्य और कृषि संबंधि सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ ही लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों का सामान भी अपने स्तर पर उपलब्ध करा रहा है। मिशन रीव के तहत लोगों को विभिन्न तरह के उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रानिक सामान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा क्रॉकरी व अन्य सामान भी लोगों को उनके घरों पर बाजार से बेहद कम दाम पर उपलब्ध कराया जा रहा है। मिशन रीव के तहत लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे विभिन्न तरह के सामान और सेवाओं से लोगों में भी काफी खुशी है। लोगों का कहना है कि पहले उन्हें छोटी छोटी चीजों को खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ रहा था लेकिन अब मिशन रीव के तहत उन्हें हर तरह की सुविधाएं घर पर ही मिल रही है। इससे उनके समय और पैसे दोनों की ही बचत हो रही है।

युवाओं को रोजगार के साथ जनसेवा का मौका

टीम रीव, हमीरपुर

हमीरपुर ज़िले में मिशन रीव के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर सेवाएं प्रदान की जा रही है। सेवाओं के साथ ही मिशन रीव ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने के सबसे बड़े मिशन की ओर अग्रसर है।

ज़िले के अभी तक सैकड़ों ग्रामीण युवा बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है तथा वे सभी ग्रामीण स्तर, खण्ड स्तर एवं ज़िला स्तर पर अपनी सेवाऐं प्रदान कर रहे हैं। अभी भी यह प्रक्रिया जारी है।

जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ज़िला में विभिन्न पंचायतों में जैविक खाद निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया । इससे किसानों में रासायनिक खाद को छोड़कर जैविक खाद बनाने व उपयोग करने की प्रक्रिया को अपनाने के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ी है। पंचायतों में फेसिलिटेटर पंचायत से संपर्क कर गांव–गांव जाकर लोगों से सीधा संपर्क साध रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानकर उनका निवारण भी कर रहे हैं। लोगों की मांग पर कम कीमत में फूलों का बीज, मटर तथा मक्की का बीज लागों को उनके घर पर ही प्रदान किया गया। ऑनलाइन सेवाओं के बारे में आम ग्रामीणों को निरंतर जागरुक किया जा रहा है तथा किस प्रकार ऑनलाइन बिजली के बिल, टेलिफोन एवं अन्य बिलों का भुगतान अपने मोबाइल से ही घर बैठे कर सकते हैं, इसकी जानकारी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को दी जा रही है।

मिशन रीव से गांव में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। लोगों को उनके घरों में डाक्टर से परामर्श की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा अगर कोई बाजार से दवाईयां लाना चाहता है तो वह भी मिशन रीव के प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है। इस सुविधा से मिलने से ग्रामीण काफी खुश है।

जन औषधि केंद्र से ग्रामीणों को राहत

खराब मौसम में भी आसानी से मिल रही दवाईयां

टीम रीव, चंबा

एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान, आईआईआरडी शिमला की एक नई पहल के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में लोगों को सस्ते दामों पर दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तीन सौ जनऔषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। इसी के तहत चंबा के तीसा में भी जनऔषधि खोला गया है। चंबा के तीसा में यह पहला जनऔषधि केंद्र है। इसके खुलने से तीसा के लोगों को अब सस्ती दवाईयों के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। खास बात यह कि चंबा इन दिनों भारी बर्फबारी की जद में है। गांव से शहरों तक पहुंचना किसी चुनौति से कम नहीं है। ऐसे में तीसा में खोला गया जनऔषधि केंद्र लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है क्योंकि मौसम खराब होने के बावजूद लोगों को इस केंद्र पर आसानी से सभी दवाईयां मिल रही है और उन्हें इसके लिए बाजार नहीं जाना पड़ रहा है। बाजार में भी अधिकतर दुकानों पर खराब मौसम के कारण सभी दवाईयां नहीं मिल पा रही, दूसरे गांवों से बाजार तक पहुंचना भी मुश्किल है। ऐसे में तीसा में खुला जनऔषधि केंद्र वहां के लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है।

तीसा के लोगों का कहना है कि अभी तक उन्हें बाजार से मंहगे दामों पर दवाईयां खरीदनी पड़ती थी। कई बार तो ये दवाईयां जेब पर इतनी भारी पड़ जाती थी कि घर का पूरा बजट ही बिगड़ जाता था। लेकिन अब आईआईआरडी की ओर से प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना के तहत तीसा में सस्ती दवाईयां उपलब्ध कराई जा रही है। इससे स्थानीय लोगों को काफी राहत है। तीसा में ही जनऔषधि केंद्र खुलने से इलाज सस्ता हो गया और लोगों के समय की भी बचत हो रही है।

महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ेगा मिशन रीव

गांव में तैयार उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में भी देगा सहयोग

टीम रीव, चंबा

किसी भी क्षेत्र के विकास में महिलाओं का विशेष योगदान रहता है। ऐसे में जरूरी है कि विकास को लेकर नई योजनाओं के बारे में ग्रामीण महिलाओं को जागरूक किया जाए। इसी उद्देश्य से मिशन रीव की ओर से चंबा की विभिन्न पंचायतों पंचायत में महिला मंडल के साथ एक विशेष बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।

इस बैठक के दौरान मिशन रीव की ओर से महिलाओं को मिशन रीव के तहत ग्रामीण विकास के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। चंबा में महिलाओं ने बताया कि गांव में अक्सर महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर का लाभ नहीं मिल पाता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि गांव में महिलाओं को योजनाओं की जानकारी नहीं होती। महिलाओं ने बताया कि वह चाहती है कि गांव में महिलाओं के कौशल को विकसित करने के लिए कुछ विशेष कदम उठाए जाए। स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर महिलाओं को प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।

इसके बाद मिशन रीव प्रतिनिधियों की ओर से बताया कि वह कैसे गांव की महिलाओं के लिए स्वरोजगार पैदा करने में सक्षम है। मिशन रीव संस्करण –2 के तहत गांव में महिलाओं को सशक्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसके तहत अगर गांव की महिलाएं समूह बनाकर कोई कार्य करना चाहती है तो मिशन रीव उसमें पूरा सहयोग करेगा। इसमें महिलाओं को उनकी रूची के मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों में बेसिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उदाहरण के लिए महिलाओं को आचार, पापड़, सिलाई–कढ़ाई समेत अन्य कई तरह के व्यवसाय शुरू करने में मदद की जाएगी। खास बात यह कि महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार भी मिशन रीव की ओर से ही उपलब्ध कराया जाएगा। महिलाओं को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। मिशन रीव की ओर से उनके घरों से ही तैयार उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।

महिला मंडल की सदस्यों की ओर से मिशन रीव की भरसक प्रशंसा की गई। महिलाओं ने कहा कि योजनाओं के बारे में बात तो सब करते हैं लेकिन इन योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त करना है यह कोई नहीं बताता। लेकिन अब मिशन रीव के तहत यह सभी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे उन महिलाओं को भी लाभ मिल रहा है जो घरेलु काम काज के कारण कहीं बाहर नहीं जा पाती। मिशन रीव के तहत पंचायत में, यहां तक की घर में ही सभी जानकारी प्रदान की जा रही है।

मिशन प्रतिनिधियों को दी बीमा योजनाओं की जानकारी

विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया आयोजन

टीम रीव चंबा

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन को सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए मिशन रीव के तहत विभिन्न कार्य किए जा रहे है। हाल ही में आईआईआरडी की ओर से भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ साझेदारी की गई है। यानि अब आईआईआरडी मिशन रीव के तहत गांव के लोगों को एलआईआसी करने के लिए अधिकृत है। इसकी शुरूआत जिला चंबा से की जा रही है। इसी के तहत चंबा में मिशन रीव के प्रतिनिधियों के लिए एलआईआसी की ओर से विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला चंबा में एलआईआसी के ब्रांच मैनेजर राजेश नैयर ने बतौर विशेष अतिथि शिरकत की। उन्होंने मिशन प्रतिनिधियों को भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। चंबा के जिला समन्वयक मिशन रीव, राकेश शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान राजेश नैयर ने हाल ही में एलआईसी की ओर से लॉच की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और साथ ही मेडीकल योजनाओं के बारे में भी बताया।

इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जीवन बीमा के बारे में किस तरह बताकर उन्हें इसका महत्व समझाया जाए, इस बारे में भी प्रशिक्षण के दौरान एलआईसी अधिकारियों की ओर से विस्तार से जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मिशन रीव के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मिशन रीव की ओर से जिला चंबा में ग्रामीण विकास को लेकर बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं। बात कृषि की हो या ग्रामीण विकास की, मिशन रीव हर क्षेत्र में अहम भूमिका अदा कर रहा है।

मिशन प्रतिनिधियों को दिए बेहतर कार्य करने के टिप्स

वीडियो कान्फ्रेसिंग से प्रबंध निदेशक ने किया मार्गदशन

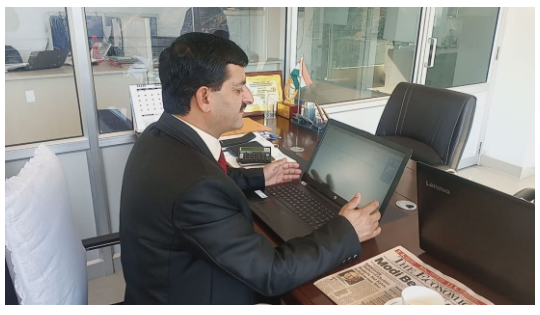

टीम रीव, चंबा

आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डाक्टर एलसी शर्मा ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से चंबा में मिशन रीव प्रतिनिधियों को बेहतर कार्य करने के टिप्स दिए। इस दौरान उन्होंने फील्ड स्टाफ से उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली और उनका समाधान भी किया। इसके अलावा मिशन रीव संस्करण –2 के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सेवाएं प्रदान करने के बारे में भी जानकारी दी गई। डाक्टर एलसी शर्मा ने बताया कि मिशन रीव के दूसरे संस्करण के तहत सेवाओं को तकनीकि से जोड़ा गया है ताकि लोगों को कम पैसों में समयबद्ध तरीके से सेवाओं का लाभ मिल सके। दूसरे संस्करण में लोगों की आवश्कताओं का आकलन करने के लिए मिशन रीव के तहत ऑनलाइन ही किया जाएगा। लोगों की आवयश्कताओं के मुताबिक उन्हें सेवाएं मुहैया कराने के लिए मिशन रीव –2 के तहत 10 सेवा प्रभागों को शामिल किया गया है। इसके तहत कृषि, स्वास्थ्य, संपत्ति, व्यवसाय समेत अन्य प्रभागों को शामिल किया गया है। इन्हीं के मुताबिक गांव के लोगों को सेवाएं प्रदान की जाएगी। इसी बारे में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रबंध निदेशक डाक्टर एलसी शर्मा ने चंबा में मिशन रीव प्रतिनिधियों को जानकारी दी और सेवाओं को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए।

ग्राम सभा में लोगों को किया जागरुक

टीम रीव, कुल्लू

कुल्लू के जगातसुख में मिशन रीव और अन्य विकासात्मक योजनाओं के बारे में लोगों को ग्रामसभा के दौरान जागरूक किया गया। ग्राम सभा के दौरान लोगों को बताया गया कि कैसे मिशन रीव के तहत विभिन्न तरह की सेवाएं गांव में लोगों को दी जा रही है। मिशन रीव के तहत ग्रामीणों के रोजमर्रा की वस्तुओं की आपूर्ति भी घर पर ही की जा रही है। साथ ही बेहतर कृषि पैदावार के लिए जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके तहत जिला कुल्लू में अभी तक सैंकड़ो किसानों को जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। प्रशिक्षण के अलावा किसानों को खाद की बिक्री के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इन सेवाओं के अलावा अन्य योजनाओं की जानकारी भी ग्रामसभा के दौरान लोगों को दी गई।

बच्चों की पढ़ाई में भी मदद करेगा मिशन रीव

संस्करण –2 में मिलेगी आधुनिक सुविधाएं

टीम रीव, मंडी

प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह मंडी में भी मिशन रीव संस्करण–2 के तहत गांव के लोगों और युवाओं को उनकी आवश्यताओं के मुताबिक सेवाएं मुहैया करवाई जाएगी। मिशन रीव के दूसरे संस्करण के तहत गांव में हर आयु वर्ग के मुताबिक गांव के लोगों को सेवाएं प्रदान की जाएंगी। सबसे खास बात यह है कि अब मिशन रीव युवाओं को उनके करियर की मजबूत नींव रखने में भी मदद करेगा। इसके लिए विशेष तौर पर शिक्षा प्रभाग को मिशन रीव की सेवाओं में शामिल किया गया है। इस प्रभाग के तहत परिवार में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने वाले छात्रों को उनकी क्षमता और रूची के मुताबिक अकादमिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर किसी बच्चे को किसी विषय विशेष में कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए मिशन रीव की ओर से विशेष प्रशिक्षण का प्रबंध किया जाएगा। इसके अलावा मनौवैज्ञानिक तौर पर भी बच्चों का आकलन कर उसे पढ़ाई में बेहतर करने में मदद की जाएगी। 10वीं कक्षा के बाद अगर किसी छात्र को उसकी रूची के मुताबिक विषय

विशेष का चयन करने और अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए कोचिंग आदि की समस्या आती है तो उसमें भी मिशन रीव ट्यूटोरियल योजना के तहत छात्रों की मदद की जाएगी। अगर अभिभावकों को लगता है कि उनका बच्चा किसी कारण से गलत संगत में पड़ गया है या किसी नशे का आदि हो गया है तो उस बच्चे को इन सभी से बाहर निकाल कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में भी पूरा सहयोग दिया जाएगा।

हाल ही में मिशन रीव के तहत एनएसडीसी और एचपीकेवीएन के साथ साझेदारी की गई है। ऐसे में अब उन युवाओं के कौशल को तराशा जाएगा जो किन्हीं कारणों से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर रोजगार से वंचित रह गए हैं। इन युवाओं को विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षित कर उनके लिए रोजगार का प्रबंध भी मिशन रीव के तहत किया जा रहा है।

कानूनी अधिकार जो हर भारतीय को पता होना आवश्यक है

- आपके एल.पी.जी गैस कनेक्शन के साथ आपको 40 लाख रूपये तक की इंश्योरेंस स्वतः मिलती है । यानि यदि आपके गैस सिलिंडर में विस्फोट होता है तो आपको 40 लाख रूपये तक का मुआवजा मिल सकता है ।

- अगर आप किसी कंपनी द्वारा भेंट किये हुए तोहफे को स्वीकार करते हैं तो आप पर कोई भी व्यक्ति रिश्वत लेने का मुकदमा चला सकता है ।
- भारत में केवल महिला पुलिस अधिकारी के पास ही महिलाओं को गिरफ्तार करके सुरक्षित थाने में ले जाने का अधिकार होता है। अगर भारत में किसी महिला को पुरुष पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करके थाने में लेकर जाता है तो इसको अपराध माना जाता है और ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कानूनी कारवाई हो सकती है ।
- अगर किसी महिला को रात के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे के समय के बीच पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा जाता है तो उस महिला को अधिकार है कि वह पुलिस स्टेशन आने से मना कर सकती है ।
- इनकम टैक्स अधिकारियों या कर वसूल करने वाले अधिकारियों के पास आपको गिरफ्तार करने का अधिकार होता है । अगर आप ने टैक्स नहीं दिया तो टी.आर.ओ (Tax Recovery Organization) के पास आपको गिरफ्तार करने का अधिकार होता है और उनकी अनुमति पर ही आप जेल से छूट सकते हैं । इस नियम का उल्लेख वर्ष 1961 के इनकम टैक्स एक्ट में किया गया है ।
- साइकिल चलाने वालों पर कोई मोटर व्हीकल एक्ट नहीं लागू होता। अगर आप रोजाना साइकिल चलाते हैं तो आपको मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन साइकिल और रिक्शा नहीं आते।
- भारत में अभी भी बहुत सारे लोग लिव–इन रिलेशनशिप को कानूनी अपराध मानते हैं। भारतीय कानून के अनुसार लिव–इन रिलेशनशिप अवैध नहीं है लेकिन लिव–इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुष और महिला को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। अगर लिव–इन रिलेशनशिप में बच्चे का जन्म होता है तो उसका माता–पिता की प्रॉपर्टी पर पूरा–पूरा अधिकार होगा।
- राजनीतिक दलों के पास चुनाव के समय आप से वाहन किराए पर लेने का अधिकार होता है। अगर आप वाहन देने के लिए तैयार हैं तो चुनाव के समय राजनीतिक दल आपसे आपका वाहन किराए पर ले सकते हैं।
- भारत में अगर आप पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की वजह से दिन में एक बार जुर्माना लग गया है तो आप पर पुलिस अधिकारी पूरे दिन फिर जुर्माना नहीं लगा सकते। उदाहरण के लिए अगर आप पर दिन में एक बार हेलमेट ना पहनने का चालान हो गया है तो रात तक आप बिना हेलमेट पहने घूम सकते हैं और ट्रैफिक अधिकारी आप पर जुर्माना नहीं लगा सकता।
- आप के पास वस्तु की अधिकतम खुदरा मूल्य से कम कीमत देने का अधिकार होता है। आप दुकानदार से कोई वस्तु सौदे के साथ भी खरीद सकते हैं जैसे कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 100 रूपये है तो आप सौदा करके उस वस्तु को 90 रूपये में भी खरीद सकते हैं।
- वर्ष 1861 में बने पुलिस एक्ट के अनुसार भारत के हर राज्य का पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर रहेगा। अगर किसी जगह पर आधी रात को भी कोई अपराध या घटना होती है तो पुलिसकर्मी को यह कहने का कोई अधिकार नहीं होता कि वह ड्यूटी पर नहीं हैं क्योंकि पुलिस एक्ट के अनुसार पुलिसकर्मी बिना वर्दी के भी हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं।
- अगर पति पत्नी में सेक्स संबन्ध अच्छे नहीं हैं तो दोनों इस वजह को तलाक के सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं ।

एडवोकेट प्रदीप वर्मा
कानूनी सलाहकार, आईआईआरडी, 94180 25649

पाठकों के प्रश्न एवं कानूनी समस्याऐं सादर आमंत्रित है। आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे कानून विशेषज्ञ ऐडवोकेट प्रदीप अगले अंक में देंगे। प्रश्न हमारी मेल आई डी पर डालें

therievtime@iirdshimla.org hem.raj@iirdshimla.org

लीवर और उससे जुड़ीं समस्याऐं

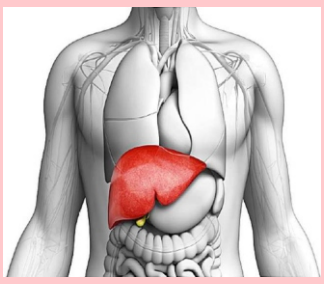

यकृत को अंग्रेजी में लीवर (Liver) कहते हैं और हिंदी में जिगर कहा जाता है। यह हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पेट के दाहिनी ओर नीचे की तरफ होता है। लिवर शरीर की बहुत सी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जिनमें खाना पचाना, शरीर से टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकालना, शरीर को एनर्जी देना, बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना आदि शामिल हैं। लीवर खराब होने पर शरीर की कार्य करने की क्षमता न के बराबर हो जाती है और लीवर डैमेज का सही समय पर इलाज कराना भी जरूरी होता है नहीं तो यह गंभीर समस्या बन सकती है।

लीवर क्या कार्य करता है :

भोजन के पाचन में लीवर का कार्य अहम् है। कार्बोहाइड्रेट्स को लिवर ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में जमा करके रखता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे ग्लूकोज के रूप में छोड़ता है। लिवर शरीर में नुकसान करने वाले पदार्थों को निष्क्रिय करता है और प्रोटीन बनाता है जिस से हम रक्तस्त्राव और इंफेक्शन से बचे रहते है। शारीरिक विकास के लिए लिवर कई प्रकार के पदार्थ बनाने में मदद करता है जैसे ग्लूकोज, खून, प्रोटीन, पित्त ।

लीवर के रोग क्या हैं

लीवर में कैंसर
पीलिया जॉन्डिस
वायरल हैपेटाइटिस
फैटी लीवर
लीवर में सूजन

लीवर की बीमारी के कारण क्या हैं

खाने पीने में लापरवाही बरतने पर लीवर से जुड़ी कई बीमारियां हो सकती हैं। गलत आदतों की वजह से लीवर खराब होने की आशंका सबसे ज्यादा होती है। जैसे शराब का अधिक सेवन करना, धूम्रपान अधिक करना, और अधिक नमक सेवन आदि।

- सिगरेट और शराब ज्यादा पीना
- दूषित मांस खाना, गंदा पानी पीना, मिर्च मसालेदार और चटपटे खाने का अधिक सेवन करना
- खाने में तेल मसाले ज्यादा प्रयोग करना
- जंक फूड का सेवन करना
- लगातार कई दिनों तक कब्ज रहना
- नकली दवाओं और एंटीबायोटिक दवाईयों का अधिक मात्रा में सेवन करना।

लीवर खराब होने पर शरीर में दिखाई देने वाले लक्षण

- पाचन तंत्र में खराबी
- पेशाब का रंग पीला होना
- पेट में सूजन आना छाती में जलन और भारीपन का होना।
- भूख न लगने की समस्या, बदहजमी होना, पेट में गैस बनना।
- लिवर वाली जगह पर दबाने से दर्द होना
- आंखों और चेहरे पर पीलापन आना
- आंखों के नीचे डार्क सर्कल बनना
- मुंह का स्वाद खराब होना और मुँह से बदबू आना
- शरीर में आलस और कमजोरी होना

लीवर की सूजन दूर करने के उपाय

- पानी का सेवन अधिक से अधिक करें।
- मीठी चीजों के सेवन से बचें ।
- रोटी की जगह हरी सब्जियां जैसे लौकी, पालक, करेला, गाजर, टमाटर और फल जैसे पपीता, आंवला, जामुन और लीची का खूब सेवन करें।
- सब्जियों में मिर्च मसाला कम से कम खाएं।
- लस्सी और छाछ का सेवन बहुत फायदेमंद रहेगा।
- घी और तेल में तली हुई चीजों का उपयोग कम से कम करें।

डॉ0 के आर शांडिल
आईआईआरडी, शिमला
अधिक जानकारी के लिए लिखें: therievtime@iirdshimla.org

ऑफिस में ऐसा होना चाहिए आपका व्यवहार

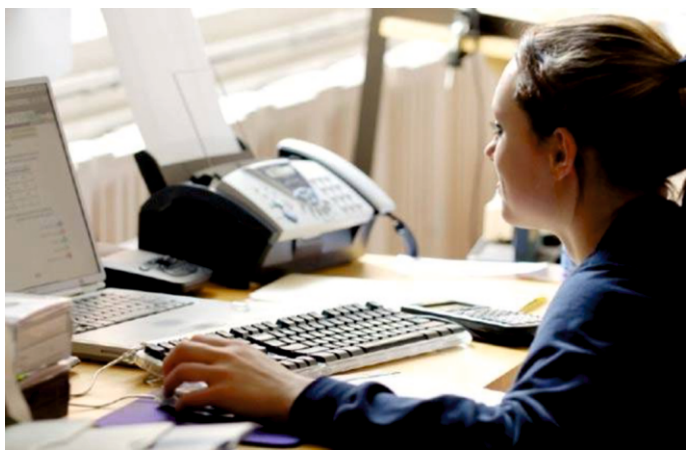

हम में से अधिकतर लोगों के दिन का एक बड़ा हिस्सा ऑफिस में गुजरता है। ऐसे में ऑफिस में अलग–अलग लोगों से आपका व्यवहार भी काफी मायने रखता है। जानिए ऑफिस में किस तरह साथ काम करने वाले लोगों से तालमेल बनाएं और कैसे व्यवहार करें ?

1. क्षेत्रीय भाषा का कम से कम करें इस्तेमाल: टीम के सदस्यों के साथ बात करते हुए और खासकर सामूहिक बैठकों में अपनी क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल न करें। टीम में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी भाषा नहीं समझते हों। ऐसे में वो लोग अलग–अलग सा महसूस करेंगे।

2. मीटिंग में समय से पहुंचे: मीटिंग में समय से न आने पर पता चलता है कि आप कितने लापरवाह हैं? इसलिए समय पर मीटिंग्स में पहुंचे। अगर आपकी मीटिंग्स एक के बाद एक करके हैं तो उनके बीच पर्याप्त अंतराल रखें।

3. साफ–सफाई का रखें ध्यान: इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ऑफिस में आपका डेस्क साफ–सुथरा रहना चाहिए। इसके अलावा खुद की भी साफ–सफाई का खास ध्यान रखें। अगर ऑफिस डेस्क गंदा रहेगा या आपका सामान बिखरा–बिखरा रहेगा तो काम करने में आपका मन नहीं लगेगा और आपके साथियों को भी परेशानी हो सकती है।

4. सीनियर्स को करें फॉलो: ऑफिस में अच्छे से सही से पेश आने का अच्छा तरीका है कि आप अपने सीनियर्स को फॉलो करें। बड़े पदों पर काम कर रहे आपके सीनियर्स आपके लिए एक उदाहरण हो सकते हैं जिन्हें फॉलों करके आप भी भविष्य में सफलता पा सकते हैं।

5. खुद को अच्छे से करें एक्सप्रेस: ऑफिस में कम्यूनिकेशन आइडियाज पर अच्छे से काम करें और खुद को अच्छे से एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपके और आपके साथियों के बीच होने वाली कई गलतफहमियां खुद ही खत्म हो जाएंगी।

6. च्यूंगम अथवा किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ न खाऐं : ऑफिस में च्यूंगम अथवा अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थ न खाऐं और धूम्रपान तो ऑफिस से बाहर जाकर भी न करें क्योंकि ऑफिस में इससे आपके कारण औरों को भी समस्या हो सकती है। साथ ही ये अच्छी आदतें नहीं हैं।

7. स्वयं से शौचालय तक रखें सफाई : जिस शौचालय का उपयोग करते हैं उसकी स्वच्छता को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है।

साभार : ऑन लाइन

विवेकहीनता का आधार... परंम्पराओं का आडंबर

इतिहास कहता है कि मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारों तलहटियों तथा मैदानी क्षेत्रों से आरम्भ हुआ। युद्ध के भय, अन्वेशण की चाह तथा एकाकी जीवन जीने आदि कारणों से एक बड़ी जन संख्या दूर दराज़ पहाड़ों की ओर जाकर बसने लगी। पहाड़ो के विस्तार तथा खुलेपन के होते हुए लोगों का बिखराव हुआ तथा कालान्तर में परिवार बड़े कुटुम्ब में तथा कुटुम्ब गांव में परिवर्तित होने लगे। क्योंकि पहाड़ों में बिखरे रूप मे बसने वाले लोगों का मैदानी क्षेत्रों में अधिक सामूहिक रूप से रहने वाली जनसंख्या में संचार साधन न होने के कारण, दूर–दूर तक कोई नाता नही रहा, जो वैचारिक उन्नति समूहों में रहने वाले मैदानी क्षेत्रों में हुई, वह पहाड़ों तक न पहुंच पाई। पहाड़ी कबीलों में शक्तिशाली व बलशाली रसूखदारों ने बहुत सारी मनगढ़ंत जीवनशैली को बढ़ावा दिया तथा कालान्तर में जो जीवन दर्शन से जुड़ी रचनाऐं भी मानव समाज को मिली। उनका भी सही से व्याख्यान न होने के कारण कई प्रकार की रुढ़ियों ने जन्म लिया जिनका मानव प्रगति से दूर–दूर तक कोई नाता नहीं। यही कारण है कि जैसे–जैसे हम दूर तक पहाड़ों की जीवन शैली देखते हैं, वैसे–वैसे तामसिक वृत्तियों का वर्चस्व अधिक दिखाई देने लगता है। जैसे कि काल्पनिक दैव्यों की पूजा, मंदिरों में लकड़ी व पत्थर की मूर्त को देवता बनाना, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाना, जीवन के दुःखों के निवारण तथा भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए तिल–जौ लेकर हवन करना आदि–आदि ऐसे ही ढेर सारी रुढ़ियां शिक्षा से अछूत मैदानी क्षेत्र में पनपी जिन्हें अब शिक्षित समाज भी जूझ रहा है । यह हमारी शिक्षा का पंगु होना दर्शाता है कि हम डिग्रियां लेकर भी समाज की रुढ़ियों जो कि हमें पीछे धकेल रही है, पर विवेकपूर्वक चर्चा करने से कतराते हैं। जहां शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्य की चिंतन शक्तियों को दीवारहीन बनाकर ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने के लिए अनुकूल बनाता है। वहीं हम परंपराओं तथा रुढ़ियों की कुछ ऐसी दीवारें बना बैठे हैं कि उन्हें दूर करना तो क्या, पर हम उन पर चर्चा करना भी अपराध समझते हैं । सदियों से आ रही इन रुढ़ियों पर समय–समय पर कई महान आत्माओं ने कुठाराघात करने के प्रयास भी किए लेकिन इनकी आधारशिला इतनी सशक्त है कि उनके सभी प्रयास बहुत तीव्रता से प्रभाव न छोड़ सके। लगभग 7000 वर्ष पूर्व श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद् गीता द्वारा इन समस्त रुढ़ियों का खण्डन किया परन्तु इनका सही भाव आज तक आम इन्सानों की पंहुच से दूर ही हैं। गीता ज्ञान को आज भी लोग पांडवों–कौरवों के मध्य के शस्त्र युद्ध के संदर्भ में देखते हैं जबकि गीता में कभी शस्त्रयुद्ध की बात नहीं की गई है। श्रीकृष्ण के बाद जीजस क्राइस्ट, गैलिलियो, सुकरात, दयानंद, विवेकानंद आदि महापुरुषों ने मनुष्य जाति को सत्य से आत्मसात करने का प्रयास किया। लेकिन सभी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। ऐसे में सदी के महान चिंतक प्रोफेसर राम कुमार गुप्ता की टिप्पणी में किसी पाश्चात्य लेखक, वैचारक का उल्लेख याद आता है कि यदि आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो इसकी कीमत अदा करने के लिए भी तैयार हो जाओ। प्रश्न यह है कि आख़िर हमने पिछले लगभग 10000 वर्षों से सीख क्या ली है ? आख़िर क्यों हम उसी मार्ग पर अग्रसर हैं जिसका कोई सशक्त नेतृत्व नहीं है अपितु भटकाव ही भटकाव है। विडंबना तो यह है कि न केवल हम सत्य को अस्वीकार कर रहे हैं अपितु असत्य को पूरी शक्ति के साथ सत्य सिद्ध करने के प्रयास कर रहे हैं। इसका नवीनतम उदाहरण कुल्लु दशहरा तथा श्री रघुनाथ मंदिर से जुड़ीं परंपरा का है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने किसी भी धार्मिक स्थान तथा उत्सव में बलि चढ़ाने की परंपरा को बंद करने के आदेश पारित किए। पहाड़ों में यह परंपरा बनी है कि देवताओ को प्रसन्न करने के लिए तथा अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए बेजुबान मेमनों, भेड़–बकरियों की मंदिरों में बलि चढ़ती है। इस बेतुकी राक्षस परंपरा से तो यही समझ आता है कि हम राक्षसों, भूतों को प्रसन्न कर रहे हैं यदि इनका अस्तित्व है तो..... न कि ईश्वरीय शक्ति को जो कभी किसी का अहित नहीं चाहती है। मनुष्य ने कभी स्वयं की बलि देने की तो नहीं सोची पर दूसरों असहायों की अवश्य ही। दूसरों असहायों की जगह यदि कभी शेरों की बलि देने की सोची भी होती तो आटा–चावल के भाव समझ में आता ! उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों ने कुल्लु दशहरे के संदर्भ में परंपराओं को ढाल बनाकर सर्वोच्च न्यायालय में अपनी दलीलें देकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को प्रभावहीन बना दिया। जिन रघुनाथ (श्रीराम) ने जीवन भर नैतिकता, सदाचार व आदर्श स्थापित करने के लिए पीड़ा सहन की, उन्हीं की आड़ में आज बेजुबान मेमनों की बलि चढ़ाने की बात से याचिककर्ताओं को क्या लाभ मिलेगा, यह समझ से परे हैं। इसकी क्या हानि हो सकती है यह अवश्य एवं सहजता से समझ आता है। कहते हैं.....प्रसन्नता बांटने से कई गुणा अधिक प्रसन्नता मिलती है तथा कष्ट बांटने से कई गुणा अधिक कष्ट की प्राप्ति होती है। मेमनों के कटने से होने वाले कष्ट अपना प्रभाव कैसे छोड़ेंगें....यह भविष्य के गर्भ में हैं। देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक वर्ष एक हज़ार से अधिक लोगों की जान भू–स्खलन तथा सड़क दुर्घटनाओं से होती है। यदि यह वास्तव में देवभूमि होती तो देवतागण इन आकस्मिक मृत्यु से रक्षा अवश्यक करते। क्योंकि हम अपने कर्मों से इसे दैत्य भूमि बनाने में लगे हैं तो इसका कोप होना अनिवार्य है। कर्मों की गति पर टीका करने वाले लोग इसे इन कुरीतियों के दुष्परिणाम के रुप में भी देखने लगे हैं। वनों को काट कर अपनी भूसंपत्ति का विस्तार कर हमने हिमालय में बैठी सभी दैविक शक्तियों को कुपित कर दिया है। अपने फलों, सब्जियों आदि के उत्पादन मे हम प्रचुर मात्रा में प्राणघातक कीटनाशकों के प्रयोग से हमने प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बैठे नारायण को कुपित करना आरंभ कर दिया है। आखिर यह कोपभाजन कहीं न कहीं तो होना ही है, तथा इसके जिम्मेवार कोई और नहीं अपितु हम स्वयं ही है। प्रकृति की इस चेतावनी को अभी भी न सुना तो यह भयावक रुप ले सकती है। मनुष्य में विवेक आए, स्वार्थपरता तथा व्यैक्तिक अहंकार से ऊपर उठकर सर्वकल्याणार्थ सेवा करें। ऐसी सामाजिक सोच एवं विचार को परिपक्कव करने की आवश्यकता है। नहीं भूलना होगा कि.....कण–कण में नारायण है।

डॉ0 एल सी शर्मा
प्रधान संपादक
md@iirdshimla.org

FROM CULTURAL DIVERSITY TO LINGUISTIC UNITY

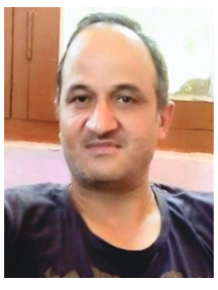

Nationalism is a term shrouded in ambiguity and appears to be an anti secular idea in India. Over the years every attempt for promotion of nationalism was portrayed as an attack on minority rights by political parties banking on this vote bank for power. Unfortunately, we as a nation failed to put up enough resistance to discourage this vicious practice of widening the gaps between communities on regional, religious or linguistic lines. For how long a country like India can hold together without anything uniting us as a country?

Walter Scott once opined: "Use of foreign language for official and educational purposes is nothing but cultural slavery." Though Hindi along with English enjoys the status of official language but for bewilderment of many, India has no National language as such. English was just the subsidiary language recommended by first official language commission of 1955 and attached considerable importance to Article 351 stating that Hindi should be so developed that it may serve as a medium of expression for all elements of the composite culture of India. It is ironical that to this day nothing has been done for promotion of Hindi, leave alone making it a National language.

If partition of India was resulted by religious intolerance, the first divide of state, contrary to aspirations of makers of constitution, was resulted by linguistic intolerance. Ever since creation of Andhra Pradesh on linguistic lines any attempt to strengthen nationalistic identity was seen as an attack on secularism. Divisive politics became a political tool thereafter for the misuse of constitution in the name of secularism.

Centre to left, all parties have been at cross purposes with right wing parties and have successfully projected nationalism as an anti constitutional and anti secular idea.

Promotion of Hindi no doubt, would have worked as an integrating gel, yoking together otherwise diverse cultures. Most states of south India along with north east states never were in consonance with idea of promotion of Hindi language. Surprisingly, states like Karnataka never used Hindi as an official language for interstate correspondence even which further emboldened them to adopt a separate state flag just like Jammu and Kashmir.

I find this to be another opening in the huge reservoir that only will erupt in coming years. Needless to add that all this leads from qualified to demand of absolute autonomy. In national interest, the 42 amendment act should have put education in the union list rather than place in concurrent list, enabling HRD to impose Hindi as a second language in school curriculum nation wide. Promotion of Hindi for national integrity would have become easier then, consequently; silencing the grunts for Dravid Nadu, an idea floated by likes of M Karunanidhi, EV Ramaswamy and CN Annadurayi to cut off entire south from rest of India.

India, very soon will replace United Kingdom as fifth largest trillion dollar economy, deserves more eminent and authoritative position in global arena. Present government wants to levitate India's presence more prominently at UN platform after procuring thumping support for International Yoga Day and re-election of Mr Bhandari for another term in ICJ, now striving for introduction of Hindi as seventh official language in UN. Hindi is fourth largest spoken language in the world after Mandarin, Spanish and English. Hindi is spoken by more than 47 percent of the total population of the country. India has World's largest diaspora who take pride in use of Hindi language, apart from this, Hindi is used by a majority of more than 20 percent of the country's total population in Nepal, Pakistan, Guyana, Suriname, Tobago, Trinidad and Mauritius, whereas Fiji is the only country with India using this for official usage. All this helps India raise this case more vociferously in the UN as other three languages, viz French, Russian and Arabic are spoken by less number of people globally. Only thing India needs right now is to win support of 129 countries in the UN but the expenditure for Hindi translation of every recorded document of the UN since its formation has to be borne by all 193 members. We can hope that India will soon earn the needed support but here even voices are raised from within against introduction of Hindi in the UN. They believe that government will impose this as a national language in India after it gets a nod from the UN as official language. Unfortunately people like Tharoor are of the view that we should not put any non-Hindi speaking future PM in a strange and embarrassing situation while addressing UN assembly. I believe, present government will ignore such insane arguments and will do whatever it takes to promote this language globally. It will be disparaging if we track back from giving this wonderful language its due just because of the inconvenience of any individual or an incompetent future PM, who fails to connect and communicate to a huge majority of India in a language they feel and think.

Entry of Hindi in the UN not only will be a glorious moment for every Indian but also will be a tribute to great linguists of this country. Only after Sanskrit, Hindi is the most scientific language of the world. NASA has brought Sanskrit in use for record keeping as they find this to be most computer friendly language. Since Hindi originates from Sanskrit, these languages share a great deal of semblance in grammar, phonology and morphology. Only draw back though with Hindi has been limited and restricted vocabulary for scientific terminology. This has been resulted by constant neglect of this language over the years by different governments in power taking pride in Lutyens culture. Ignoring this language permanently will take us to a no return point and we will only regret eternally for the loss of this treasurer.

Great linguists of this country have produced such a perfect language that never needed to undergo any changes. Every alphabet is pronounced and there are no silent sounds in this language. Unlike English, Hindi has a perfect alphabetical pattern making it most comprehensible language, where mode, manner and place of articulation fall in order. Other than Hindi and sanskrit, most languages lack expressions and do not have range of alphabets to cover all kinds of articulations humans can possibly utter. To my understanding, all other languages lack phonetic riches to assimilate the articulations falling in 'ta varg' or variety of nasal occlusions that Hindi can offer to her speaker.

Considering world wide acceptance for Hindi, government of India must act judiciously by imposing Hindi as a national language and for her own merits should be elevated to a lofty status by introducing it as the seventh official language of the UN. A country divided in caste, religion, regions and various other 'isms' can only be united by a language spoken country wide. Or, for how long can a country like India bear with this divide of secular Kannada and communal Hindi? Mahatma Gandhi for sure did not create planet earth or India in 1940s, still, if we can have a father of Nation without any provision or mention in our constitution, should we not have a National language that our constitution guides us for?

Kamlesh Sharma, Shimla (HP)
(Guest Writer) 9817540956

गठबंधन का गठजोड़ गड़बड़झाला

देश हित नहीं मोदी विरोध की प्राथमिकता है गठबंधन का आधार

मोदी सरकार को भी पड़ रहे हैं पसीने

भारत का लोकतंत्र कई मायनों में अपनी विशिष्टताओं एवं असाधारण विशेषताओं के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस लोकतंत्र की अपनी बहुत सी खूबियां है। लोकतंत्र यानि लोगों की भागीदारी और सपनों का तंत्र ....। हम अपने प्रतिनिधियों का चयन कर सरकार को चुनते हैं और कभी न पूरी होने वाली उम्मीदों की चाह में साल दर साल निकालते रहते हैं। इस प्रकार हमारा लोकतंत्र बचपन से जवान हो गया और अब जो जवानी से भी आगे की ओर तीव्रता से अग्रसर है। ऐसे में एक यक्ष प्रश्न सामने ये आता है कि 1947 के बाद आज भी हम आधारभूत उम्मीदों को पूरा होने की राह ताक रहे हैं। सरकारें आने से पहले पानी की तरह तरल, बेरंग और शीतलता लिए मतदाताओं के पास आती है और बन जाने के बाद सपनों को पूरा करने के लिए बगले झांकती रहती है। नियमित विकास कार्यों को करने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया से होकर नहीं गुजरना होता है। किंतु विकास और आमजन को सामाजिक और आर्थिक मज़बूती प्रदान करने के लिए एक अलग और दूरगामी सोच को परिणित करने की आवश्यकता होती है। ऐसा करने के लिए लोकतंत्र में एक ही ब्रह्मास्त्र है ..... हमारा वोट। इसी वोट में किसी भी राष्ट्र का हित समाहित होता है।

भारत का भविष्य भी हर पांच वर्ष में मतदाताओं के हाथ में आता है। लेकिन विडंबना देखो उस भाग्य निर्माता को अपना सबसे बड़ा अधिकार या हथियार भी असमंजस की स्थिति में डालना पड़ता है। क्योंकि यह देश इतनी विविधता लिए हुए है कि यहां हर राज्य में भिन्न–भिन्न क्षेत्रिय दलों की सरकारें हैं तथा उनके मतदाताओं का भी एक विशिष्ट वर्ग है। ऐसे में केन्द्र में अब तक सत्ताओं का खेल भी निराला ही रहा है। आज़ादी के बाद एक बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने देश की बागडोर अपने हाथ में रखी। ऐसा भी दौर आया जब विपक्ष नाममात्र का ही था। किंतु समय एक सा कभी नहीं रहता है। कांग्रेस ने भी वो दौर देखा जब देशवासियों ने इसे सत्ताहीन कर दिया और नए विकल्पों के पनपने की संभावनाऐं पैदा की। इसी का परिणाम गठबंधन या गठजोड़ लेकर सामने आया।

गठबंधन है क्या :

मूलतः भारत में गठबंधन की राजनीति का आगाज़ 1989 के आसपास होता है जब कांग्रेस की सरकार राज्यवार अपना प्रभुत्व गंवाती गई और क्षेत्रिय राजनीति का प्रादुर्भाव होना आरंभ हुआ। कांग्रेस के हाथों से सत्ता धीरे–धीरे खिसकने लगी। वहीं 1990 तक ये क्षेत्रिय दल राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाने में कामयाब होने लगे। अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख गिराती जा रही कांग्रेस के लिए चुनौती यही थी कि इन क्षेत्रिय दलों से कैसे निपटे और किस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर सरकार में बना रहा जाए ? यहीं से गठजोड़ की गड़बड़झाला शुरु होता है। राजनैतिक गठबंधन दो प्रकार से किए जाते हैं ....एक चुनावों से पहले किया गया गठबंधन और दूसरा चुनावों के बाद किया गया गठबंधन। समीकरणों को देखते हुए राजनैतिक दल अपनी गोटियां फिट करते हैं। स्थिति जैसी गठबंधन वैसा ....किंतु सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिरने से परहेज नहीं किया जाता है।

2014 के चुनावों में जिस प्रकार कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था.....ठीक उसी प्रकार 1989 में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा ही चरम पर था। चुनावों के बाद गठबंधन की सरकार बनी जिसे राष्ट्रीय मोर्चा के नाम से जाना जाता है और जिसमें जनता दल कांग्रेस, तेलगुदेशम पार्टी, असम की क्षेत्रिय पार्टी असम गण परिषद शामिल हुई। विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। वे 1988 में गठित किए गए जनता दल के अध्यक्ष भी थे। इससे पहले वे कांग्रेस में वित्त मंत्री थे। लेकिन कांग्रेस के बोफोर्स तोप घोटाले के कारण पार्टी छोड़कर उन्होंने जनता दल की स्थापना की। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को दोनों वामपंथी दलों के साथ–साथ भारतीय जनता पार्टी का भी बाहरी समर्थन हासिल था। अगस्त 1990 में आरक्षण की आग में यह सरकार भी झुलस गई और अंततः सदन में बहुमत साबित न कर पाने के कारण विश्वनाथ प्रताप सिंह को इस्तीफा देना पड़ा।

इसके बाद जनता दल में भी विघटन हो गया और 58 लोकसभा सदस्यों को साथ लेकर एक नई सरकार का गठन हुआ जिसमें चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री और देवी लाल को उप–प्रधानमंत्री बनाया गया। 7 महीने के बाद 1991 में कांग्रेस ने समर्थन वापिस लेकर इस सरकार को भी धड़ाम कर दिया और पुनः चुनावों का बिगुल बज गया। 1991 में हालांकि चुनावों में राजीव गांधी का चेहरा कांग्रेस का तुरप था, फिर भी चुनाव प्रचार के दौरान ही तमिलनाडु के पेरम्बदूर में लिट्टे के आत्मघाती विस्फोट में राजीव गांधी की हत्या हो गई। उस दौरान दक्षिण भारत में चुनाव नहीं हुए थे। हत्या के बाद वहां सहानुभूति के कारण कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा जबकि उत्तर भारत में चुनाव पहले हो चुके थे जहां कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन नहीं था। हालांकि यह तकनीकि तौर पर गठबंधन की सरकार नहीं थी फिर भी सरकार को झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे क्षेत्रिय दलों का सहारा था। पी वी नरसिंम्हा राव के नेतृत्व में सरकार ने अपने पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा किया।

1996 के लोकसभा के बाद के घटनाक्रम गठबंधन की पूरी राजनैतिक उठापठक के गवाह रही है। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और कुल 140 सीटों पर सिमट गई। तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी को 16 मई 1996 को सरकार बनाने का न्योता दिया जो कि 13 दिन बाद 1 जून 1996 को लड़खड़ाकर गिर गई। उसके बाद एच डी देवेगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा का गठन और सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनी जो कि 11 महीने तक चली। कांग्रेस ने यहां भी शयमात का खेल जारी रखा और 21 अप्रैल 1997 को यह सरकार समर्थन वापसी के कारण गिर गई और दूसरे संयुक्त मोर्चे की सरकार आई के गुजराल के नेतृत्व और कांग्रेस के समर्थन में बनी।

इस सरकार के गठन के बाद राजीव गांधी हत्या में गठित आयोग की रिपोर्ट में जब यह बात सामने आई कि राजीव गांधी की हत्या में लिट्टे के साथ तमिलनाडु की डी एम के सरकार का हाथ था तो कांग्रेस ने केन्द्र में डी एम के मंत्रियों को हटाने की मांग की जिसे गुजराल सरकार ने स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस ने इस सरकार से भी समर्थन वापिस ले लिया और सरकार गिर गई।

1998 की 12वीं लोकसभा के लिए बीजेपी ने क्षेत्रिय दलों को साथ लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन का गठन किया तथा पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला परंतु सबसे अधिक सीटें इस गठबंधन के हिस्से में आई। बहरहाल अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बन तो गई पर 13 का आंकड़ा एक बार फिर से बीजेपी और वाजपेयी के लिए मनहूसियत का अंक बन कर आया। गठबंधन में शामिल एआईडीएमके पार्टी ने समर्थन वापिस ले लिया और सरकार अल्पमत में आकर गिर गई। 1999 में फिर से 13 का अंक आया जब 13वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए लेकिन इसमें लोकतांत्रिक गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला जिससे वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार ने पांच साल का कार्यकाल पूरा किया। यहां 13 अक्तुबर 1999 को ही वाजपेयी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। यहां दीगर बात यह है कि किसी भी गठबंधन की यह पूर्ण कालिक यानि पांच साल चलने वाली पहली सरकार थी।

2014 में भी गठबंधन का गठजोड़ जारी रहा और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार का गठन किया। यहां भी गठबंधन सरकार की कश्ती भंवर में डांवाडोल होती रही। भारत द्वारा अमेरिका के साथ किए गए परमाणु समझौते के कारण वामपंथी दल नाराज़ हो गए और सरकार से समर्थन वापिस ले लिया। किंतु कुछ अन्य दलों की मदद से मनमोहन सिंह सरकार ने पुनः अपना बहुमत सदन में साबित कर दिया। इसी दौर में नरेगा जिसे बाद में मनरेगा कर दिया गया जैसी योजना ने सरकार को 100 दिन की रोजगार गारंटी के साथ खूब प्रशंसा दी और 2009 में पुनः सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में सत्ता पर काबिज़ हुई। इस गठबंधन सरकार में 15 के लगभग राजनैतिक दल शामिल थे।

गठबंधन सरकारों के अनुभव

गठबंधन सरकारों के अनुभव दोनों ही तरह से खट्टे–मीठे अनुभवों के साथ रहे हैं। गठबंधन की सरकारें क्षेत्रिय दलों के सहयोग से बनती है। लिहाज़ा उनमें क्षेत्रिय मुद्दों एवं संकीर्ण विकास की सोच तो रहती ही है। इससे क्षेत्रिय हित राष्ट्रहित पर भारी पड़ जाते हैं और नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ता है। इसके साथ ही सरकार का अधिकतर समय भिन्न–भिन्न दलों के नेताओं को मनाने और समझाने में चला जाता है। एक लंबा दौर रुठने–मनाने और मंत्री बनने की होड़ व खींचतान में व्यतीत हो जाता है।

आर्थिक और सामाजिक आधार पर देश के लिए सोच संकीर्ण होनी आरंभ हो जाती है। और विकास राज्य की सीमाओं में ही सिमटने लग जाता है। वहीं मंत्री किसी एक पार्टी के नहीं होते हैं बल्कि वो भिन्न राजनैतिक दलों के होते हैं जिससे विकास नहीं हो पाता है। विभिन्न राजनैतिक दलों में सांमजस्य स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। लेकिन एक पक्ष इसका ये भी है कि एक दल की सरकार में सभी राज्यों का विकास प्रभावित होता ही है क्योंकि राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें योजनाओं और सरकारी फरमानों को ज़्यादा तरहीज़ नहीं देती है। इसका नुकसान ये होता है संतुलित विकास नहीं हो पाता है, और गठबंधन में यह आसान हो जाता है क्योंकि सबकी यही मंशा होती है कि अपने–अपने राज्यों के लिए अधिक से अधिक अनुदान और योजनाओं को ले जाया जा सके ।

2019 में महागंठबधन का गड़बड़झाला

2014 के लोकसभा चुनावों में गुजरात को एक आदर्श मॉडल के रुप में विश्वभर में सामने रख कर नरेन्द्र मोदी और भाजपा ने मोदी लहर को आमजन तक सोशल मीडिया में सामने रखा। नतीजा ये हुआ कि मोदी की लहर के आगे विपक्ष की छतें उड़ गई और 'अच्छे दिन आऐंगें' के उद्घोष के साथ मोदी का करिश्मा प्रचंड बहुमत के साथ सामने आया। पहले तो देश, फिर विश्व भर में मोदी ने सभी भारतीयों को एकजुट कर भारत का ऐसा डंका बजाया कि धीरे–धीरे करते पूरे भारत के राज्य भगवामय हो गए। नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने विपक्षी पार्टी के सारे समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। 2014 से 2019 आते–आते भाजपा का मोदी के सहारे चलते रहने और बहुत से वायदों को अभी भी अमलीजामा न पहनाने के कारण लोगों ने तीन बड़े राज्यों में अभी हाल ही में जो झटका बीजीपी को दिया.....उससे पार्टी के कान खड़े हो गए हैं। फिर उप चुनावों में मिली हार को भी विपक्षी पार्टियों ने खूब भुनाया । इससे मोदी मैजिक को विपक्ष झुटलाकर जुमलेबाज और चौकीदार चोर है...जैसी निम्नस्तरीय भाषा और प्रचार के माध्यम को चुनकर लोगों के बीच उतर रहा है। अब यहां यह देखना होगा कि नरेन्द्र मोदी देश में आज भी सबसे अधिक पंसद किए जाने वाले नेता है तथा विदेशों में भी उनकी धूम बरकरार है। पॉपूलेरिटी में उनके आसपास भी देश में कोई नेता नहीं है ।

राहुल की अपरिपक्वता...

अब विपक्ष की अप्रत्यक्ष कमान राहुल गांधी ने संभाल रखी है। उन्होंने इस बार संसद में काफी हद तक बोलना भी सीख लिया लेकिन मोदी के गले लगने जिसे बाद में गले पड़ना भी कहा गया ....के बाद आंख मारने के अंदाज़ पर अपरिपक्कवता का आभास करवा दिया। ऐसा एक नहीं बल्कि दो बार करने पर भी राहुल को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। नतीजन उनके सामने–सामने देश के अन्य क्षेत्रिय दलों का गठबंधन होना शुरु हो गया। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्यप्रदेश की जीत कांग्रेस को जीवनदान दे दिया लेकिन उनके सामने ही उत्तर प्रदेश जहां से सरकारें बनती और बिगड़ती है.....वहां बुआ भतीजे का गठजोड़ हो गया। कभी गेस्ट हाउस कांड में आजीवन दुश्मन बने सपा और बसपा आज मोदी ख़ौफ एक ही गले से बोल रहे हैं। इसमें राहुल के लिए कोई स्थान होगा.....भविष्य में कोई संभावनाऐं फिलहाल तो नहीं है परन्तु मोदी को हटाने के लिए विपक्षी दल किसी भी हद तक जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जातिगत और अल्पसंख्यक वर्ग को लुभाने में मायावती ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जिसमें अपने पिता मुलायम को दरकिनार कर अखिलेश भी हाथी की पूंछ पकड़कर चल रहे है। उधर पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने ताबड़तोड़ रैलियों और भाषणों से ममता की बादशाहत को चुनौती दी है। बात यहां तक पहुंच गई कि अमित शाह का हैलिकॉप्टर तक वहां उतरने के लिए सरकार की स्वीकृति करता रहा और फिर एक निजि होटल के टेरेस पर उतारना पड़ा। ममता बनर्जी ने महागठबंधन में स्वयं को आगे रखने और मोदी सरकार को हर हाल में उखाड़ने के लिए कमर कस रखी है। उनके महासम्मेलन में विपक्षी दलों का जमवाड़ा तो लगा ही साथ ही बीजेपी के बागियों ने भी जमकर मोदी सरकार को कोसा।

अब देखना यह है कि ऐसा क्या हुआ जिससे धुर प्रतिद्वंद्वी भी एक दुसरे को गले लगाने के लिए आतुर है। यदि विकास नहीं हुआ तो रिपोर्ट के अनुसार क्यों भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी और तीव्रता से आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है ? मेक इन इंडिया में भी निवेश बढ़ा है, परिवहन और सड़कों के अलावा औद्योगिक केन्द्रों में भी रफ्तार पकड़ी है। उधर देश भर में सरकार की आरक्षण के प्रति सोच को लेकर स्वर्ण जातियों का हल्ला बोल जारी रहा और कई राज्यों में तो इसका ख़ामियाज़ा भी भुगतना पड़ा। इससे आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण स्वर्णों के लिए देकर मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चला दिया। लेकिन अच्छे दिन आए या नहीं इसका आकलन अब 2019 में अपने अधिकार यानि वोट का प्रयोग करने से पहले देशवासियों को करना शेष है ।

विपक्ष के साथ अपने बागी भी...

सोशल मीडिया में राजनीति का स्तर जिस प्रकार देश और व्यक्तिगत तौर पर निम्न स्तर पर आ गया है इससे मतदाताओं को भी आकलन में दिक्कत हो रही है। इधर राहुल गांधी अभी अपने गठजोड़ में छोटे दलों को साथ लेने के लिए आतुर है तो मायावती भी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का लक्ष्य मन में संजोए है। उधर बंगाल में ममता अब दिल्ली की ओर आने के सपने बुनने में लगी है तो बिहार से लालु और कंपनी राजनीति का बिगुल भी मोदी को हर हाल में बाहर करने के लिए बजा रहे हैं। इसमें बागी शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार का मोह मन में संजोए बीजेपी में रहते हुए ही राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाने आरंभ कर दिए हैं। भाषा और प्रचार का स्तर इस कद्र निम्न हो गया है कि पहले चुनावों में बीजेपी को हराओ फिर प्रधानमंत्री तो कोई भी बन सकता है। इधर कांग्रेस ने अपने तरकश से ब्रह्मास्त्र चला दिया जो कि पर्दे के पीछे से हर चुनावों में चलाया जाता रहा है। प्रियंका को चुनावों में उतारना और पार्टी में महासचिव बनाकर सामने लाने से राहुल को भी आलोचनाओं से गुजरना पड़ा। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने तो एक साक्षात्कार में स्पष्ट की कह दिया कि राहुल ने यह स्वीकार कर लिया है कि उनके बस की अब बात नहीं रही..... उन्हें प्रियंका को आगे लाना पड़ा। हालांकि राजनीतिक पंडितों का यह कहना भी वाज़िब है कि प्रियंका के पास इंदिरा गांधी से सूरत मिलने के अलावा कोई अन्य अनुभव नहीं है। उधर राहुल ने राफेल को संसद से सड़क और सड़क से गली–मुहल्लों में चौकीदार चोर हैं के नारे के साथ प्रचारित करने का जो बीड़ा उठाया है.....वो उन पर ही भारी पड़ता नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी तक राहुल कुछ भी साबित नहीं कर पाए। मात्र भ्रम में पार्टी के कार्यकर्ताओं और लोगों को डालने की कलाबाजियां कर रहे हैं।

विरोध के ये अवसर स्वयं मोदी सरकार ने भी विपक्षियों को दिए हैं। बीजेपी को कहने और करने में बहुत बड़े अंतर से बचना होगा। लोग अच्छे दिनों की तलाश में मोदी सरकार लाए थे जिसे सरकार पूरा करने में काफी हद तक कामयाब हुई....ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन नोटबंदी, जीएसटी और कड़े कानून बनाकर अपराध व भ्रष्टाचार के लिए विपक्षियों को पानी पिलाने के बाद चिरविरोधी भी कुड़माई की रस्म निभाने के लिए गले मिल गए हैं। बहुत से नेताओं को तो जेल की हवा खानी ही पड़ रही है लेकिन डर यह भी है कि 2019 में यदि सरकार की पुनरावृति होती है तो स्थितियां और अधिक प्रतिकूल हो सकती है। इसलिए गठबधन का गड़बड़झाला देश के लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति पर सभी का एक साथ प्रहार ... महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरने जैसा तो लगता है लेकिन यह समझना बाकि है कि अभिमन्यु के चेहरे के पीछे अर्जुन तो नहीं ....

हेम राज चौहान
सहायक संपादक, द रीव टाइम्स
Chauhan.hemraj09@gmail.com,94184 04334

आम बजट से हिमाचल के 8.45 लाख छोटे किसानों को होगा फायदा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल के छोटे किसानों के लिए मोदी का आम बजट खुशियां लेकर आया है। भले ही उनकी फसल खिले या मुरझाए, मोदी सरकार उनकी जेब में हर साल छह हजार रुपये राशि डालेगी। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में दो हेक्टेयर से कम काश्त वाले 8.45 लाख किसान जबकि कुल किसानों की संख्या 9.68 लाख तक है। प्रदेश में छोटी काश्त है। प्रदेश में किसानों और बागवानों की संख्या प्रदेश की कुल आबादी का अस्सी फीसदी तक है।

जयराम कैबिनेट ने केंद्रीय बजट को बताया ऐतिहासिक, बैठक में लिए ये बड़े फैसले

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2018–19 का अनुपूरक बजट पेश करने की मंजूरी प्रदान की गई। चार फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर भी मुहर लगाई गई। मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक करार देते हुए तारीफ की। बैठक में चार मंत्री सरवीण चौधरी, विपिन सिंह परमार, बिक्रम ठाकुर और किशन कपूर अनुपस्थित रहे।

कैबिनेट ने बजट में किसानों, गरीबों, महिलाओं, छात्रों, व्यापारियों और मध्यम वर्ग के लिए की कई बड़ी घोषणाओं की सराहना की हैं। बैठक में असंगठित क्षेत्र के कम से कम 10 करोड़ मजदूरों और श्रमिकों को पेंशन लाभ प्रदान करने और आयकर सीमा में 5 लाख रुपये तक की छूट, स्टांप शुल्क में सुधार और रक्षा बजट को 3 लाख करोड़ से अधिक करने की भी सराहना की गई।

केरल की विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा हिमाचल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार के कार्यक्रम 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत' (ईबीएसबी) के तहत केरल के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि दोनों राज्यों में कई समानताएं जैसे सर्वोत्तम साक्षरता दर, अच्छे सामाजिक संकेतक, पर्यटन, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आयुर्वेद आदि हैं। प्रधान सचिव शिक्षा केके पंत ने यह बात यहां ईबीएसबी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक में विभिन्न हितधारक विभागों के नोडल अधिकारियों ने भाग लिया।

शिमला में स्वाइन फ्लू से बढ़ी मौतें सूबे में अब तक जा चुकी है कई जानें

द रीव टाइम्स ब्यूरो

स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, सबसे अधिक मामले कांगड़ा में आए हैं। यहां 27 मरीजों को स्वाइन फ्लू हुआ है। इसके अलावा, बिलासपुर में पांच, चंबा में चार, सोलन में तीन, ऊना में दो, मंडी में पांच, हमीरपुर में तीन लोगों को इस बीमारी की पुष्टि हुई है।

हिमाचल प्रदेश में स्वाइन फ्लू से एक और मौत हुई है। मृतक हमीरपुर का रहने वाला है। बता दें कि साल 2019 के पहले महीने में ही सबसे बड़े अस्पताल पळडब में रिकॉर्ड तोड़ मरीज पहुंचे हैं। आईजीएमसी प्रबंधन ने मृतक की पहचान बताने से इंकार कर दिया है।

अस्पताल में अब तक पहले माह में ही 139 मामले आए हैं, जिनमें 44 मरीजों में स्वाइन फ्लू के लक्षण पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल, अस्पताल में 12 मरीजों का उपचार चल रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों शिमला, सोलन, बिलासपुर, कुल्लू, हमीरपुर और मंडी जिला से आए मरीजों में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए हैं।

कुल्लू पुलिस ने 2 किलो से ज्यादा चरस और 40 ग्राम हेरोइन के साथ 5 युवकों को पकड़ा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कुल्लू पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने दो चरस तस्करों के कब्जे से 2 किलो 225 ग्राम चरस बरामद की है और 40 ग्राम हेरोइन के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है।

कुल्लू पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने दो चरस तस्करों के कब्जे से 2 किलो 225 ग्राम चरस बरामद की है और 40 ग्राम हेरोइन के साथ तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। 27 ग्राम हेरोईन के साथ फोजल निवासी महेंद्र और 13 ग्राम हेरोईन के साथ मणिकर्ण के रणजीत को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।

शिमला में चिट्टे के साथ दो युवक गिरफ्तार, रिमांड पर भेजे गए

पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, दोनों से पूछताछ जारी है कि यह नशे की सामग्री कहां से लाए थे।

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दो युवकों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शोघी के पास बीते दिनों को दो युवकों को 13 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया।

इनमें से एक आरोपी दीपक चौहान (20) सिरमौर से है और दूसरा आरोपी रोनु कुमार (25) मंडी का रहने वाला है। दोनों को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से तीन दिन के रिमांड पर भेजा गया है।

पुलिस के अनुसार, पुलिस शोघी के पास गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी को पुलिस ने रोका तो दोनों युवक घबरा गए. इसके बाद पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो 13 ग्राम चिट्टा मिला।

एचएएस की मुख्य परीक्षा में 109 पास

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा –2017 का परिणाम घोषित किया है। इस परीक्षा में 109 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। 52 पद भरने के लिए यह परीक्षा आयोजित की थी। आयोग की संयुक्त सचिव एकता कपटा ने बताया कि परीक्षा में पास उम्मीदवारों का अब पर्सनलिटी टेस्ट होगा।

एमेजॉन पर बिकेंगे हिमाचली उत्पाद

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बंगलूर में उद्योगपतियों को हिमाचल आने का न्योता दिया और सब उम्मीद के अनुरूप रहा तो विश्व की सबसे बड़ी ई–कॉमर्स कंपनियों में से एक एमजॉन जल्द ही परंपरागत हिमाचली उत्पाद ऑनलाइन बेचती नजर आएगी। हिमाचल सरकार द्वारा बंगलूर में आयोजित रोड–शो के दौरान स्वयं एमजॉन ने इस संबंध में इच्छा जताई ।

बजट लोस चुनाव के लिए अंतिम जुमला

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बोले, भाजपा ने आमजन–किसानों से फिर किया फरेब

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा पेश अंतरिम बजट आम आदमी व किसान के लिए निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों के लिए यह बजट उनके अंतिम जुमले के रूप में अच्छी तरह से साबित हुआ है। इससे आमजन ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं।

हिमाचल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने देवेश कुमार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय निर्वाचन आयोग ने देवेश कुमार को प्रदेश का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। निर्वाचन आयोग ने हिमाचल सरकार को इसकी सूचना भेज दी है। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि नए सीईओ को अन्य दायित्वों से शीघ्र मुक्त कर दिया जाए ।

इससे पहले इस पद का कार्यभार डीके रत्न के पास था। हिमाचल सरकार की ओर से आयोग के पास तीन आईएएस अफसरों देवेश कुमार, पूर्णिमा चौहान और अजय शर्मा के नामों का आयोग को पैनल भेजा गया था ।

इसके बाद भारतीय निर्वाचन आयोग ने देवेश कुमार के नाम पर मुहर लगाई। आईएएस अधिकारी देवेश कुमार वर्तमान में सचिव आईपीएच के पद पर नियुक्त हैं।

आदेश नहीं मान रहे निजी स्कूल

शिक्षा विभाग को 20 साल बाद भी 429 विद्यालयों ने नहीं भेजी ऑडिट रिपोर्ट, डिपार्टमेंट कसेगा शिकंजा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रदेश के निजी स्कूलों पर अब शिक्षा विभाग के आदेशों को सख्ती से न लेना भारी पड़ेगा । 20 सालों बाद शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूलों से आडिट रिपोर्ट मांगे जाने पर भी आधे–अधूरे स्कूलों ने ही यह रिपोर्ट विभाग को भेजी है। हैरानी है कि चार जिलों के एक भी स्कूल से ऑडिट का ब्यौरा नहीं आया है। हालांकि बाकी जिलों से आधे–अधूरे स्कूलों ने अपने सीए विभाग से स्कूल का ब्यौरा ऑडिट भेज दिया है । जानकारी के अनुसार शिमला, कांगड़ा, लाहुल व कुल्लू जिलों के एक भी निजी स्कूल ने ऑडिट रिपोर्ट भेजने में आनाकानी की है । विभाग के इन निर्देशों को न मानने पर विभाग उक्त जिले के स्कूलों को नोटिस जारी कर उन पर कार्रवाई करेगा । बता दें कि उच्च शिक्षा निदेशक ने इस बारे में संबधित अधिकारियों को निजी स्कूलों की लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। हैरानी है कि 20 साल बाद अब जब शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों पर नजर रखने के लिए ऑडिट रिपोर्ट मांगी है, तो तब भी निजी स्कूल बिलकुल भी गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं।

बंदर मारने को फिर मांगी अनुमति

प्रदेश सरकार ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजा रिमाइंडर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में बंदरों के आतंक से काबू पाने के लिए वन विभाग फिर से असमंजस की स्थिति में हैं। विभाग ने प्रदेश सरकार से अवगत करवाया था कि बंदरों को मारने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगें। वन विभाग की सिफारिश पर ही सरकार ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को हाल ही में प्रदेश की 53 तहसीलों को वर्मिन घोषित करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन केंद्र ने यह पूछा था कि पूर्व में कितने बंदर मारे गए।

वन विभाग नहीं, जनता मारेगी

पिछले फार्मूले की तर्ज पर ही बंदरों को वन विभाग नहीं, बल्कि आम आदमी खुद मारेगा । यानी जिन लोगों को खतरा है या नुकसान हो रहा है तो वही लोग बंदरों को मार सकेंगे। हालांकि अभी वर्मिन घोषित होने में समय लग सकते हैं, लेकिन बंदरों को मारने का तरीका ऐसा ही रहेगा।

बंदर मार कर लाओ, पांच सौ रुपए पाओ

प्रदेश सरकार ने बंदरों को मारने के लिए भी राशि तय की है। एक बंदर मारने पर पांच सौ रुपए मिलेंगे। इसके लिए भी शर्त यह है कि मारा गया बंदर दर्शाना पड़ेगा। इसके साथ–साथ एक बंदर पकड़ कर लाने वाले व्यक्ति को सात सौ रूपये दिए जाएंगे। यह प्रावधान पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय से है।

आईजीएमसी में स्वाइन फ्लू के बाद डेंगू का पहला मामला

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राज्य के आईजीएमसी में स्वाइन फ्लू के बाद अब डेंगू के मामले भी सामने आने लग गए है। मनाली की रहने वाली एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। महिला की रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है ।

जबकि महिला को अस्पताल की ओपीडी में उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। मनाली की रहने वाली महिला बीते दिनों बुखार, शरीर में दर्द की समस्या लेकर अस्पताल में इलाज करवाने आई थी ।

अब ग्राम सभाओं में जलपान जरूरी

कोरम पूरा न होने पर भी पंचायतें खर्च सकेंगी प्रति व्यक्ति 50 रुपए

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग ने ग्राम सभाओं व ग्राम पंचायत की बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों को जलपान करवाना अनिवार्य कर दिया है। अब पंचायतें ग्राम सभा व बैठकों में प्रति व्यक्ति 50 रुपए जलपान के लिए खर्च कर सकेंगी। इतना ही नहीं, अब ग्राम सभाओं का कोरम पूरा न होने पर भी पंचायतें मौजूद सदस्यों पर जलपान के लिए निर्धारित राशि खर्च कर सकती हैं।

टैक्स में 5 लाख आय तक छूट: हिमाचल में ढाई लाख से ज्यादा कर्मचारी, बड़े तबके को फायदा !

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी कल्याण संघ का कहना है कि इस फैसले से कर्मचारियों को खासा फायदा होगा। केंद्र सरकार का यह सकारात्मक फैसला है।

केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट यानी अंतरिम बजट आज संसद में पेश किया है। सरकार ने इस बजट में सबसे बड़ा फैसला टैक्स रिबेट को लेकर किया। केंद्र सरकार ने पांच लाख की आय को ट्रैक्स फ्री करने का ऐलान किया है. इस फैसले हिमाचल को खासा फायदा होगा। हिमाचल में कर्मचारियों की संख्या ढाई लाख से ज्यादा है और कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग को इस फैसले से खासा फायदा है।

अब पार्टी हाईमान तक जाएगा BJP पार्षद और डिप्टी मेयर के बीच का हंगामा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश की राजधानी में शिमला नगर निगम की मासिक बैठक के दौरान हुई झड़प के बाद बीजेपी पार्षद और डिप्टी मेयर के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सदन में हुई गहमागहमी को लेकर अब डिप्टी मेयर पार्टी हाईकमान से शिकायत कर पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे।

तेज रफ्तार ने बरपाया कहर भेड़ों के झुंड पर बस चढ़ने से 28 की मौत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

शनिवार सुबह गद्दी अपनी भेड़ों के झुंड को ले जा रहे थे तभी घालुवाल की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार बस ने भेड़ों को कुचल दिया। ऊना के झलेड़ा में एक तेज रफ्तार बस ने भेड़ के झुंड को कुचल दिया। इस हादसे में 28 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 22 भेड़े इस हादसे में घायल हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

हिमाचल आने को उत्साहित बड़े औद्योगिक घराने

हैदराबाद में राइजिंग हिमाचल रोड शो, सीएम से चर्चा के बाद 150 से ज्यादा कंपनी प्रतिनिधियों ने दिए निवेश के संकेत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में 85 हजार करोड़ रुपए निवेश जुटाने की सरकारी मुहिम सफलता की ओर बढ़ती नजर आ रही है। यही कारण है कि अपोलो हॉस्पिटल, डाक्टर रेड्डीज लैब, आईटीसी लिमिटेड, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन, ग्रीनको और माइक्रोमैक्स मोबाइल जैसी कंपनियों ने प्रदेश में निवेश की संभावनाएं तलाशी हैं। बंगलूर में सफल इन्वेस्टर रोड शो के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने कुशल सहयोगियों के साथ गुरुवार को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पहुंचे, जहां देश की दिग्गज कंपनियों के उच्च पदस्थ प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मिले और हिमाचल में निवेश करने की इच्छा जताई। अपोलो हॉस्पिटल प्रदेश के दूरवर्ती क्षेत्रों में टेलिमेडिसिन को बढ़ावा देने को उत्सुक हैं, तो डाक्टर रेड्डीज लैब बद्दी में उद्योग विस्तार करना चाहती है। नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी होटल, सड़कों, पुलों और सुरंगों के निर्माण में सहभागिता निभाना चाहती है, तो ग्रीनको प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा भंडारों की स्थापना को लालायित है। इन्वेस्टर मीट के दूसरे दिन हैदराबाद में गुरुवार को राइजिंग हिमाचल–2019 का रोड शो आयोजित किया गया।

अंतरिम बजट 2019–20

केन्द्रीय वित्त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वर्ष 2019–20 के लिए 01 फरवरी 2019 को पेश किए गए अंतरिम बजट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं–

वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाएं

1. किसान

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दो हेक्टेयर तक की जोत वाले सभी सीमांत किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता 2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में लाभार्थी किसान के बैंक में सीधे हस्तांतरित कर दी जाएंगी। इससे 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम से 75,000 करोड़ का वार्षिक व्यय होगा।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर 750 करोड़ रुपये किया गया

गऊ संसाधनों के अनुवांशिक उन्नयन को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया जाएगा।

1.5 करोड़ मछुआरों के कल्याण के लिए अलग मत्स्य पालन विभाग

पशुपालन और मछली पालन कार्यों में लगे किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का लाभ, इसके अतिरिक्त ऋण का समय पर भुगतान करने पर उन्हें 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी।

2. श्रम

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कामगारों के लिए निश्चित मासिक पेंशन के तहत केवल 100/55 रुपये का प्रति माह अंशदान देने पर 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रति माह 3000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन।

3. स्वास्थ्य

22वां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हरियाणा में स्थापित किया जाएगा।

4. मनरेगा

मनरेगा के लिए 2019–20 में 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन।

5. प्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्ताव

5 लाख रुपये तक की आय को आयकर से छूट

मध्यम वर्ग के 3 करोड़ करदाताओं के लिए 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की कर राहत

मानक कटौती को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया।

बैंक/डाकघरों में जमा धनराशियों से अर्जित ब्याज पर टीडीएस की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये की जा रही है।

आयकर की वर्तमान दरें जारी रहेंगी

अपने कब्जे वाले दूसरे घर पर अनुमानित किराये में कर छूट

आवास और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा

किराये पर स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती की सीमा 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2,40,000 करने का प्रस्ताव

पूंजीगत लाभ के पुनर्निवेश पर मिलने वाली छूट का दायरा 2 करोड़ रुपये तक के पूंजीगत लाभ अर्जित करने वाले करदाताओं के लिए एक आवासीय मकान से दो आवासीय मकान तक बढ़ाया जाएगा

सस्ते आवास के लिए कर लाभ की अवधि अब आयकर कानून की धारा 80–आईबीए के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाई जा रही है।

बिना बिकी संपत्ति के अनुमानित किराये पर आयकर की छूट एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया

6. राजकोषीय कार्यक्रम

वर्ष 2019–20 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4 प्रतिशत

राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य 2020–21 तक हासिल किया जाएगा

राजकोषीय घाटे को 2018–19 आरई में घटाकर 3.4 प्रतिशत तक लाया जाएगा, जो 7 वर्ष पूर्व करीब 6 प्रतिशत था

वर्ष 2019–20 में कुल व्यय को 13 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ाकर 27,84,200 करोड़ रुपये पर लाया जाएगा

वर्ष 2019–20 के लिए पूंजीगत व्यय 3,36,292 करोड़ रुपये होने का अनुमान है

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए आवंटन वर्ष 2019–20 में बढ़कर 3,27,679 करोड़ रुपये होगा

राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए वर्ष 2019–20 में आवंटन करीब 20 प्रतिशत बढ़ाकर 38,572 करोड़ रुपये किया गया.

एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के लिए आवंटन 18 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 27,584 करोड़ रुपये किया गया

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटन में पर्याप्त वृद्धि–

अनुसूचित जाति के लिए आवंटन में 35.6 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 76,801 करोड़ रुपये किया गया, जो 2018–19 में 56,619 करोड़ रुपये था

अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटन में 28 प्रतिशत की वृद्धि कर 2019–20 में इसे 50,086 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि 2018–19 में यह 39,135 करोड़ रुपये था

सरकार को विश्वास है कि वह 80 हजार करोड़ को विनिवेश लक्ष्य को हासिल कर लेगी

राजकोषीय घाटा समेकन कार्यक्रम के साथ ऋण समेकन पर विशेष ध्यान

7. गरीब और पिछड़ा वर्ग

देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का: वित्त मंत्री

गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को पूरा करने के लिए शिक्षण संस्थानों में 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें।

शहरों और गांव के बीच की खाई को पाटने और गांवों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए लक्षित व्यय।

सभी इच्छित परिवारों को मार्च 2019 तक बिजली के कनेक्शन प्रदान किये जाएंगे।

8. पूर्वोत्तर

2018–2019 के बजट अनुमानों की तुलना में 2019–20 बजट अनुमानों में 21 प्रतिशत तक की वृद्धि करते हुए आवंटन को 58,166 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जायेगा

अरूणाचल प्रदेश ने हाल ही में वायु मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज की

मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ने पहली बार भारत के रेल मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज की

ब्रह्मपुत्र नदी की उन्नत नौवहन क्षमता के माध्यम से कंटेनर कार्गो का आवागमन

9. वंचित वर्ग

सभी शेष गैर–अधिसूचित घुमन्तू और अर्द्ध–घुमन्तू जन–जातियों की पहचान के लिए नीति आयोग के अंतर्गत एक नई समिति

गैर–अधिसूचित घुमन्तू और अर्द्ध–घुमन्तू जन–जातियों के विकास और कल्याण के लिए समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक नवीन कल्याण विकास बोर्ड

10. रक्षा

रक्षा बजट में पहली बार 3,00,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार किया

11. रेल

बजट से 2019–20 (अनुमानों) में 64,587 करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता का प्रस्ताव किया गया

समग्र पूंजी व्यय कार्यक्रम 1,58,658 करोड़ रुपये किया गया

संचालन अनुपात के वर्ष 2017–18 98.4 प्रतिशत से 2018–19 के 96.2 प्रतिशत और 2019–20 (बजट अनुमानों) में 95 प्रतिशत तक सुधार

12. मनोरंजन उद्योग

भारतीय फिल्म निर्माता, फिल्मों की शूटिंग में सहायता के साथ–साथ एकल खिड़की स्वीकृति सुविधा प्राप्त कर सकेंगे

स्व–घोषणा पर और अधिक भरोसे के लिए नियामक प्रावधान

चोरी पर नियंत्रण करने के लिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में एंटी–कैमकॉर्डिंग प्रावधान की प्रस्तुति

13. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं व्यापारी

जीएसटी पंजीकृत एसएमई उद्यमों के लिए एक करोड़ रुपये के वृद्धिशील ऋण पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट

सरकारी उपक्रमों में 25 प्रतिशत में से कम से कम 3 प्रतिशत महिला स्वामित्व वाले लघु और मध्यम उद्यमों के लिए होगा

आंतरिक व्यापार पर अधिक ध्यान देते हुए डीआईपीपी को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग का नाम दिया गया

14. डिजिटल ग्राम

सरकार अगले पांच वर्षों में 1 लाख ग्रामों को डिजिटल ग्रामों में परिवर्तित करेगी

15. अन्य घोषणाएं

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की सहायता के लिए एक नवीन राष्ट्रीय आर्टिफिशियल पोर्टल का गठन

करोड़ रुपये के खर्च से 15 एकड़ में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक का निर्माण किया गया है। गांधीजी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी को इसका उद्घाटन किया।

रक्षा मंत्रालय ने 40 हज़ार करोड़ रुपये की 6 पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की

रक्षा मंत्रालय ने 31 जनवरी 2019 को भारतीय नौसेना के लिए 40 हजार करोड़ रुपये की लागत से छह पनडुब्बियों के स्वदेश में निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

रक्षा मंत्रालय की यह परियोजना रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत पूरी की जाएगी जो विदेशी रक्षा निर्माताओं के साथ मिलकर भारत में चुनिंदा सैन्य प्लेटफॉर्म बनाने के लिए निजी फर्म को जिम्मेदारी देने की व्यवस्था करता है।

लांस नायक नजीर अहमद वानी को मरणोपरांत अशोक चक्र

देश की रक्षा करते हुए शहीद लांस नायक नजीर अहमद वानी को मरणोपरांत अशोक चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी और मां को गणतंत्र दिवस (Republic Day) के मौके पर यह सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों सम्मान लेते समय नजीर अहमद वानी के परिजन भावुक हो गए। वानी को मिले इस सम्मान पर उनके परिजनों ने भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया था।

प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख तथा भूपेन हज़ारिका को भारत रत्न

राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी जानकारी में घोषणा की गई कि वर्ष 2019 में तीन हस्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया जायेगा। इस घोषणा में नानाजी देशमुख, भूपेन हज़ारिका और प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, मशहूर संगीतकार भूपेन हजारिका और आरएसएस से जुड़े नेता एवं समाजसेवी नानाजी देशमुख को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन से जारी बयान में कहा गया कि नानाजी देशमुख एवं भूपेन हजारिका को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने रिसर्च फेलोशिप की राशि बढ़ाने की घोषणा की

केंद्र सरकार ने 30 जनवरी 2019 को रिसर्च फेलोशिप की राशि बढ़ाने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को रिसर्च स्कॉलर्स की संशोधित फेलोशिप राशि संबंधी सूचना जारी कर दी है। यह बढ़ोतरी एक जनवरी 2019 से लागू होगी। केंद्र सरकार ने भौतिक और रासायनिक विज्ञान सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणितीय विज्ञान, कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान, फार्मेसी आदि किसी भी क्षेत्र में दाखिला लेने वाले पीएचडी छात्रों और अन्य अनुसंधान कर्मियों की फेलोशिप बढ़ाई है।

पूर्व रक्षामंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का निधन

भारत के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का 29 जनवरी 2019 को नई दिल्ली के मैक्स अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। दिल्ली में उन्होंने सुबह 7 बजे आखिरी सांस ली। जॉर्ज फर्नांडिस लंबे समय से बीमार चल रहे थे, वो अल्जाइमर नाम की बीमारी से परेशान थे। वाजपेयी सरकार के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस देश के रक्षामंत्री रहे थे. अंतिम बार वे अगस्त 2009 से जुलाई 2010 के बीच तक राज्यसभा सांसद रहे थे। फर्नांडिस ने भारत सरकार में रक्षा मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय जैसे कई अहम विभाग संभाले थे।

भारत ने PISA–2021 में शामिल होने के लिए OECD के साथ समझौता किया

केंद्र सरकार ने 2021 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (PISA) में भाग लेने का फैसला लिया है। इसके फैसले

अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (PISA) में भाग लेने का फैसला लिया है। इसके फैसले के तहत भारत सरकार और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम का आयोजन करेगा जिसके लिए भारत ने भी शामिल होने की इच्छा जताते हुए संगठन के साथ समझौता किया है।

यूएई तथा सऊदी अरब ने संयुक्त डिजिटल करेंसी Aber लॉन्च की

संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने हाल ही में संयुक्त डिजिटल करेंसी 'अबेर' (Aber) लॉन्च की है। इस संयुक्त डिजिटल मुद्रा का उपयोग दोनों देशों के मध्य ब्लॉकचेन तथा डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के बीच वित्तीय भुगतान के लिए किया जायेगा। इस डिजिटल मुद्रा के द्वारा वित्तीय विनिमय के लिए एक और विकल्प उपलब्ध होगा। आरंभ में इस मुद्रा का उपयोग सीमित बैंकों में किया जायेगा, बाद में इसे धीरे–धीरे अन्य स्रोतों द्वारा भी उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने दांडी में 'नमक सत्याग्रह स्मारक' का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी 2019 को गुजरात के सूरत और दांडी का दौरा किया। यहां उन्होंने सूरत हवाईअड्डे पर टर्मिनल भवन के विस्तार परियोजना और एक अस्पताल की आधाशिला रखी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान दांडी में 110 करोड़ रुपये के खर्च से 15 एकड़ में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक का निर्माण किया गया है। गांधीजी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी को इसका उद्घाटन किया। अब यह स्मारक जनता के लिए खोल दिया गया है।

सिक्किम में पहली स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन

केन्द्रीय पर्यटन मंत्री के.जे. अल्फोंस ने सिक्किम में पहली स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया. इस परियोजना को मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत लागू किया गया है। केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने इस की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत लागू किया गया है। केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने इस परियोजना को 98.05 करोड़ रुपये की लागत से जून 2015 में मंजूरी दी थी. इस योजना के अंतर्गत सिक्किम में यह पहली परियोजना हैं। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय ने पर्यटन बुनियादी ढांचा सुविधाएं जैसे पर्यटन सूचना केन्द्र, ध्यान केन्द्र, ऑर्गेनिक इको पर्यटन केन्द्र, लॉग हट, जिप लाइन, फूलों के लिए प्रदर्शनी केन्द्र, उद्यान पथ, स्मारिका दुकानें, कैफेटेरिया, बारिश से बचने की जगह, सड़क के किनारे सुविधाएं, अंतिम मील तक संपर्क पार्किंग, सार्वजनिक शौचालय आदि विकसित किए है।

चित्रा मुद्गल सहित 24 लेखक साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित

हिन्दी की प्रसिद्ध लेखिका चित्रा मुदगल सहित 24 लेखकों को 29 जनवरी 2019 को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अकादमी के अध्यक्ष एवं कन्नड़ के प्रख्यात नाटककार चंद्रशेखर कम्बार ने इन लेखकों को वर्ष 2018 के लिए यह प्रस्कार प्रदान किये।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

द रीव टाइम्स संस्थापक: डॉ. एल.सी. शर्मा, द रीव टाइम्स पब्लिकेशन के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक श्री प्रदीप कुमार जरेट द्वारा एसोसिएट प्रैस सायबू निवास समीप सेक्टर -2, बस स्टैंड मिडल मार्केट न्यू शिमला-9, हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुद्रित
प्रधान सम्पादक: डा. एल.सी. शर्मा
फोन न. 0177 2640761, मेल: editor@themissionriev.com
RNI Reference No. 1328500

अमेरिका में 129 भारतीय छात्र गिरफ्तार सुषमा स्वराज से ट्विटर पर मदद मांग रहे हैं दोस्त और परिजन

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

अमेरिका में भारतीय दूतावास ने 'पे एंड स्टे' विश्वविद्यालय वीजा घोटाले में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए गए 129 भारतीय छात्रों की मदद के लिए 24x7 हॉटलाइन शुरू की है। गौरतलब है कि अमेरिका में बने रहने के लिए एक फर्जी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए गिरफ्तार किए गए 130 विदेशी छात्रों में 129 भारतीय हैं। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय दूतावास के दो वरिष्ठ अधिकारी दो नंबरों 202–322–1190 और 202–340–2590 पर चौबीस घंटे उपलब्ध रहेंगे।

विदेश मंत्रालय को मिले 16 हजार करोड़ रुपये चीन को रोकने के लिए मालदीव पर लगाया भारत ने दांव

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

वित्त वर्ष 2019–20 के अंतरिम बजट में विदेश मंत्रालय के लिए 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है। यह पिछले बजटीय आवंटन से एक हजार करोड़ रुपये से भी अधिक है। इसमें मालदीव तथा अफ्रीकी देशों की मदद के आवंटन में भारी वृद्धि की गई. दूसरे देशों की सहायता के लिये आवंटित राशि 5,545 करोड़ रुपये से 902 करोड़ रुपये बढ़ाकर 6,447 करोड़ रुपये कर दी गई है। मालदीव के लिए आवंटन 125 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 575 करोड़ रुपये हो गया है। संशोधित आंकड़ों के अनुसार मालदीव को 2018–19 में देश ने करीब 440 करोड़ रुपये की मदद की।

रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण बंदरगाह चाबहार के लिये आवंटन पिछले बजट के 150 करोड़ रुपये पर स्थिर रखा गया है। भूटान के लिए आवंटन पिछले बजट के 2,650 करोड़ रुपये की तुलना में कम होकर 2,615 करोड़ रुपये पर आ गया है। इसके साथ ही अफगानिस्तान के लिये 325 करोड़ रुपये, बांग्लादेश के लिये 175 करोड़ रुपये, श्रीलंका के लिये 150 करोड़ रुपये और मंगोलिया के लिये पांच करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। नेपाल के लिए आवंटन 50 करोड़ रुपये से बढ़कर 700 करोड़ रुपये और म्यामां के लिये 280 करोड़ रुपये से बढ़कर 400 करोड़ रुपये हो गया है।

हबल अंतरिक्ष टेलिस्कोप ने ब्रह्मांड में बौनी आकाशगंगा का पता लगाया

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

हबल अंतरिक्ष टेलिस्कोप ने तीन करोड़ प्रकाश वर्ष दूर, हमारे ब्रह्मांड में पीछे की ओर मौजूद एक बौनी आकाशगंगा का पता लगाया है। बौनी आकाशगंगा में दूसरी आकाशगंगाओं की तुलना में काफी कम तारे होते हैं। इन तारों की चमक और तापमान का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने के बाद खगोलविदों ने पाया कि ये तारे आकाशगंगा के तारामंडल का हिस्सा नहीं हैं बल्कि उससे करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं। ब्रह्मांड की यह पड़ोसी आकाशगंगा आकार में बहुत छोटी है। यह आकाशगंगा के एक छोटे–से हिस्से जितनी है। शोधकर्ताओं ने बताया कि यह ना केवल बहुत छोटी बल्कि धुंधली भी है। यह शोध 'मंथली नोटिसिस ऑफ द रॉयल एस्ट्रॉनोमिकल सोसायटी: लेटर्स जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

ईरान में होविज मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण 1,200 किमी तक छुड़ाएगी दुश्मनों के छक्के

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

ईरान ने 1979 की इस्लामिक क्रांति की वर्षगांठ के अवसर पर 1,350 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक मार करने वाली नई क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सरकारी टीवी चौनल ने मिसाइल परीक्षण का प्रसारण किया। टीवी के अनुसार देश के रक्षा मंत्री आमिर हातमी का कहना है, ''होविज क्रूज मिसाइल का 1,200 किलोमीटर मारक क्षमता का परीक्षण सफल रहा। उसने सटीक निशाना लगाया।''

उन्होंने कहा, ''यह मिसाइल न्यूनतम समय में तैयार हो सकती है और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है।'' हातमी ने होविज मिसाइलों को ईरान के लंबे हाथों की संज्ञा दी है। यह मिसाइल 2015 में 700 किलोमीटर दूरी की मारक क्षमता के साथ विकसित सुमार श्रेणी के क्रूज मिसाइलों का हिस्सा है।

श्रीलंका में वीजा शर्तों के उल्लंघन के आरोप में 73 भारतीय गिरफ्तार

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

श्रीलंकाई अधिकारियों ने वीजा शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में इस साल 73 भारतीयों को गिरफ्तार किया है । आव्रजन एवं प्रवासी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यहां से करीब 60 किलोमीटर दूर माटुगामा में एक फैक्ट्री से कुल 49 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया उन्होंने बताया कि वे वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी रह रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि पिछले महीने इंगिरिया में एक फैक्ट्री में काम करने वाले 24 भारतीयों को वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी देश में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार भारतीयों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भारत भेजा जाएगा।

फिलीपींस–द्वीप पर इतनी शांति कि लोग घरों में अक्सर पानी भरा होने के बाद भी यहां से जाने को तैयार नहीं

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

- फिलीपींस के उबे द्वीप पर घरों में साल में करीब 130 दिन पानी भरा रहता है
- समुद्र जलस्तर बढ़ रहा फिर भी लोग यहां रहना चाहते हैं

फिलीपींस का उबे द्वीप एक अलग तरह की समस्या से जूझ रहा है। यहां ज्वार आने पर समुद्र का पानी घरों में घुस जाता है। साल के लगभग 130 दिन यही हालात रहते हैं, लेकिन यहां शांति इतनी है कि लोग इस जगह को छोड़कर जाने को तैयार नहीं हैं।

यहां लोगों ने ज्वार के पानी से सामान बचाने के तरीके भी तलाश लिए हैं। वे पालतू जानवरों को बांस के मचान पर रख देते हैं। स्कूलों में बच्चों के बैग रखने के लिए आलमारियां बनाई गई हैं। फर्नीचर गीले न हों, इसलिए उनके पाए लंबे कर दिए गए हैं।

ब्रिटिश संसद में कश्मीर मुद्दे पर कार्यक्रम भारत ने जताया कड़ा विरोध

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

- पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जम्मू–कश्मीर के मुद्दे पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हर मंच पर भारत के द्वारा मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के मंच पर जम्मू–कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है। लंदन में ब्रिटिश संसद के अंदर जम्मू–कश्मीर से जुड़ा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के शामिल होने की संभावना है। भारत ने इस इवेंट का कड़ा विरोध जताया है।

इस मसले पर ब्रिटिश हाई कमीशन का कहना है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी प्राइवेट विजिट पर लंदन आ रहे हैं, इस दौरान वह कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कमीशन की ओर से कहा गया है कि उनका सरकार के साथ किसी तरह की आधिकारिक मुलाकात का कार्यक्रम नहीं है।

कश्मीर के मुद्दे पर ब्रिटिश हाई कमीशन ने कहा कि ये जम्मू–कश्मीर के मसले का हल सिर्फ भारत–पाकिस्तान ही बातचीत कर निकाल सकते हैं। हालांकि, संसद में होने वाले कार्यक्रम पर कमीशन ने कहा कि संसद में कोई भी सांसद किसी तरह का इवेंट आयोजित कर सकता है, सरकार उसे बाध्य

अमेरिका – ठंड से 29 की मौत अगले कुछ हफ्तों में अचानक बढ़ सकता है तापमान

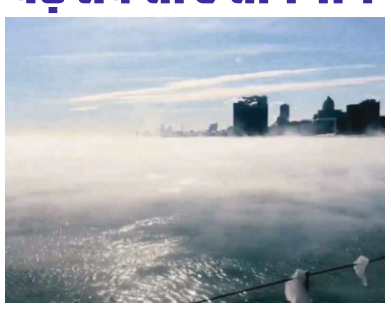

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

- दो दिनों में तापमान में 27 डिग्री की वृद्धि, पारा बढ़ने से बाढ़ का खतरा
- इससे पहले बुधवार को शिकागो में माइनस 30 डिग्री तापमान था, ट्रेनें चलाने के लिए पटरियों पर आग लगानी पड़ी थी

आर्कटिक ब्लास्ट के चलते अमेरिका में बर्फबारी जारी है। पोलर वोर्टेक्स (ठंडी हवाओं) की वजह से शुक्रवार को भी कुछ इलाकों में पारे में काफी गिरावट देखी गई। ठंड की वजह से अलग–अलग इलाकों में अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि यहां जल्द ही मौसम में काफी बदलाव आने वाला है। कुछ ही हफ्तों बाद तापमान में काफी वृद्धि होने की संभावना है। कुछ इलाको में तापमान 26 डिग्री तक पहुंच सकता है। इससे यहां बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है।

खुलासा: केबिन में स्मोकिंग कर रहा था पायलट इसलिए हुआ था काठमांडू हादसा

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

बीते साल नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुए विमान हादसे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सामने आई जांच रिपोर्ट के मुताबिक, विमान का पायलट अपने केबिन में स्मोकिंग कर रहा था जो कि हादसे की मुख्य वजह बना। बीते साल मार्च में यूएस–बांग्ला एयरलाइंस का विमान लैंडिंग के समय हादसे का शिकार हो गया था, इस हादसे में 51 लोगों को जान चली गई थी।

जांच रिपोर्ट के मुताबिक, यूएस–बांग्ला एयरलाइंस की नीति नो स्मोकिंग की रही है। इसके बावजूद फ्लाइट के पायलट इन कमांड ने उड़ान के वक्त स्मोकिंग की। ये खुलासा फ्लाइट के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से हुआ। रिपोर्ट ने साफ किया कि मार्च 2018 को जो भी हादसा हुआ वह सिर्फ और सिर्फ क्रू की गलती के कारण ही हुआ था, अगर लापरवाही नहीं बरती गई होती शायद हादसा नहीं होता। इतना ही नहीं रिपोर्ट ने ना सिर्फ विमान के क्रू बल्कि त्रिभुवन एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर को भी जिम्मेदार ठहराया ।

मेक्सिको: तेल पाइपलाइन में हुए धमाके से अब तक 73 लोगों की मौत, 74 घायल

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

मेक्सिको में एक तेल पाइपलाइन में हुए धमाके में कम से कम 73 लोगों की मौत हो गई और 74 लोग घायल हो गए । माना जा रहा है कि हिडालगो राज्य के तलाहुलिलपान शहर में संदिग्ध तेल चोरों ने पाइपलाइन को तोड़ दिया था, जिसके बाद शुक्रवार रात यह धमाका हुआ।

पाइपलाइन में उस समय आग लग गई, जब कई लोग वहां लीक हो रहे तेल को इकट्ठा कर रहे थे। इस दौरान सशस्त्र बल भी वहां मौजूद थे। हिडालगो के गवर्नर उमर फयाद ने कहा कि धमाके के बाद आग लग गई। मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडर ने इस हादसे के बाद ईंधन चोरी को रोकने के लिए उपाय करने का संकल्प लिया है।

बहामास में जहाज डूबने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हुई

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

बहामास में एबैको तट पर जहाज डूबने के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है. अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है । रॉयल बहामास रक्षा बल ने बताया कि दो दिन के बचाव अभियान के बाद अब तक कुल 17 लोगों को जिंदा बचाया जा चुका है और 28 शव बरामद किये गए हैं । हादसा शनिवार को हुआ था जब हैती के नागरिकों को ले जा रहा जहाज एबैको के मार्श हार्बर तट से दस किलोमीटर दूर फॉल केय के नजदीक डूब गया था ।

सोमालिया में अमेरिका का हवाई हमला अल–शबाब के 24 आतंकी ढेर

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

अमेरिकी सेना ने सोमालिया में आतंकवादी ठिकाने पर किए हवाई हमले किए। जिसमें अल–शबाब आतंकी संगठन के करीब 24 आतंकवादी मारे गए। अल–शबाब वहां का कुख्यात आतंकी संगठन है। जिसने वहां कोहराम मचा रखा है। ये आतंकी समूम कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है, जिन्होंने पूरे अफ्रिका को ही नहीं बल्कि दुनिया को हिलाकर रख दिया था।

इस हमले से प्रभावित इलाके में हड़कंप मच गया । आतंकियों ने सोचा नहीं था कि अमेरिका की तरफ से अचानक ऐसी कार्रवाई की जा सकती है ।

दुनिया का सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है दुबई

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कहना है कि वह अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अब भी दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बना हुआ है । एयरपोर्ट ने सोमवार को कहा कि उसने 2018 में 8.9 करोड़ यात्रियों का स्वागत किया।

दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने तबसे अपनी इस उपलब्धि को बरकरार रखा है और यहां से करीब 75 एयरलाइंस अपनी उड़ानों को संचालित करती हैं । जॉर्जिया में हार्ट्सफील्ड–जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कुल मिलाकर दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना हुआ है ।

अगले साल अमेरिका में होंगे राष्ट्रपति पद के चुनाव

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अभियान और संबद्ध समितियों ने 2018 के अंतिम तीन महीनों में 2.1 करोड़ डॉलर का भारी फंड जमा कर 2020 में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव के चक्र में प्रवेश कर लिया है।

चुनाव लड़ने के लिए इकट्ठा किए इतने पैसे

एक मीडिया रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई। द वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार, गुरुवार रात सार्वजनिक किए गए संघीय चुनाव आयोग (एफईसी) के नए बयान बताते हैं कि ट्रंप दोबारा चुनाव लड़ने के लिए अब तक 12.9 करोड़ डॉलर इकट्ठा कर चुके हैं जो कि किसी पद पर बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए रिकॉर्ड है ।

ईरान के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में आग, तीन वैज्ञानिकों की मौत

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

ईरान के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में लगी आग में तीन वैज्ञानिकों की मौत हो गई। यह जानकारी वहां की अर्द्ध सरकारी समाचार एजेंसी आइएसएनए ने दी। दूरसंचार मंत्री एमजेए जहरोमी के हवाले से रविवार को रिपोर्ट में बताया गया कि अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के एक भवन में आग लगने के कारण तीन वैज्ञानिकों की मौत हो गई। गौरतलब है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में सहयोग के लिए अमेरिकी आलोचना के बावजूद एक उपग्रह को कक्षा में भेजने की योजना बनाई थी। जनवरी में देश ने एक उपग्रह का प्रक्षेपण भी किया था।

वैलेंटाइन डे पर नीलाम होगा 72 साल पहले गिरा उल्कापिंड, जानिए क्यों है खास

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

72 साल पहले अंतरिक्ष से गिरे उल्कापिंड को वैलेंटाइन डे पर नीलाम किया जा सकता है । यह उल्कापिंड दिल के आकार का है । ब्रिटिश नीलामी घर क्रिस्टी इस खास दिन पर दिल के आकार के उल्कापिंड की ऑनलाइन नीलामी करने जा रहा है । कहा जा रहा है कि इसकी कीमत इसके वजन के आधार पर निर्धारित की जाएगी ।

बता दें कि वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले 12 फरवरी, 1947 को यह उल्कापिंड साइबेरिया में गिरा था । इसे हर्ट ऑफ स्पेस नाम दिया गया है । इस उल्कापिंड की नीलामी छह फरवरी से शुरू होकर 14 फरवरी को खत्म होगी । नीलामी घर को दिल के आकार वाले इस उल्कापिंड की तीन से पांच लाख डॉलर में बिक्री का अनुमान है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक

द रीव टाइम्स

- केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट 2019 में इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर जितने लाख रुपए कर दी गई–5 लाख रुपए
- बजट 2019 में घर किराए से आय पर टीडीएस की सीमा को 1.8 लाख रुपए से बढ़ाकर जितने लाख रुपए किया गया है–2.4 लाख रुपए
- वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश अंतरिम बजट 2019–20 की अहम घोषणाओं में से एक पीएम किसान योजना है जिसके तहत सीमांत किसानों को जितने हजार रुपये प्रति वर्ष की सहायता राशि दी जाएगी–6000 रुपये
- बजट 2019 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर जितने करोड़ रुपये कर दिया गया है–750 करोड़ रुपये
- वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश अंतरिम बजट 2019–20 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए जितने हज़ार करोड़ रुपये आवंटित किये गए है–19 हज़ार करोड़ रुपये
- बजट–2019 भाषण में गायों की सुरक्षा को लेकर जिस आयोग की स्थापना की घोषणा की गई है– राष्ट्रीय कामधेनु आयोग
- बजट–2019 में रक्षा बजट की घोषित राशि है– 3 लाख करोड़ रुपये
- बजट–2019 में जिस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जमीन रखने वाले किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की गई है–प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना
- बजट 2019 के भाषण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इतनी राशि आवंटित करने की घोषणा की गई है–19 हज़ार करोड़ रुपये
- पीयूष गोयल द्वारा पेश किये गये विज़न–2030 में निहित आयामों की संख्या है–10
- वह पूर्व रक्षा मंत्री जिसकी अगुवाई में 1974 में देश की सबसे बड़ी रेलवे हड़ताल का आह्वान किया गया था–जॉर्ज फ़र्नांडिस
- लंदन की कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी रिपोर्ट में इस कम्पनी को भारत की सबसे मूल्यवान कम्पनी घोषित किया गया है–टाटा ग्रुप
- वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (ँ।) द्वारा हाल ही में जारी एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार स्टील उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान है–दूसरा
- वह राज्य जहां 250 सरकारी स्कूलों में 11,000 नई कक्षाओं के निर्माण का उद्घाटन किया गया है–दिल्ली
- वह स्थान जहां का हवाई अड्डा विश्व का सबसे अधिक व्यस्त रहने वाला हवाई अड्डा है–दुबई
- भारत में 11 साल पहले मिले सुपरबग से जुड़े जीन इसंछक्ड–1 की इस स्थान पर पहचान सुनिश्चित हो पाई है –आर्कटिक
- दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेज़ोस के एरोस्पेस स्टार्टअप का नाम जिसने अमेरिका में रॉकेट इंजन के अपने नए प्लांट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है – ब्लू ओरिजिन
- कॉफीहाउस चेन 'स्टारबक्स' के पूर्व सीईओ का नाम है जिन्होंने हाल ही में कहा है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए गंभीरता से विचार कर रहे हैं – हॉवर्ड शुल्ज़
- यूएन जॉइंट ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने कहा है कि इस देश में 50 से अधिक सामूहिक कब्रों को खोजा गया है–कांगो
- भारत की क्रिकेट टीम ने हाल ही में इस देश की टीम के खिलाफ 10 वर्ष बाद उसके ही घरेलू मैदान पर सीरीज जीतने में कामयाबी हासिल की है –न्यूजीलैंड
- केंद्र सरकार ने पीएचडी छात्रों को मिलने वाली रिसर्च फेलोशिप में बढ़ोतरी करते हुए जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) को 25,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर जितने रुपये प्रति माह कर दिया है–31,000 रुपये
- जिस आईआईटी टीम ने नदी की धारा से बिजली बनाने वाला डिवाइस टेस्ट किया– आईआईटी–रूड़की
- केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने जिस राज्य के कोटपूतली स्थित आदर्श विद्या मंदिर में सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया– राजस्थान
- केन्द्रीय पर्यटन मंत्री के.जे. अल्फोंस ने जिस राज्य में पहली स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया– सिक्किम
- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए 'वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक' में जिस देश को 78वें स्थान पर रखा गया है– भारत
- वह लेखक जिन्हें हाल ही में श्रीलाल शुक्ल स्मृति साहित्य सम्मान दिया गया–रामधारी सिंह दिवाकर
- वह राज्य सरकार जिसने 'प्रोजेक्ट गौशाला' के तहत राज्य में अगले चार महीने में 1,00 गौशालाएं खोलने का निर्णय लिया है–मध्य प्रदेश
- वर्ष 2019 के अंतरिम बजट जिनके द्वारा पेश किया गया उनका नाम है–पीयूष गोयल
- वह अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसके द्वारा आयोजित कराये जाने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (PISA)–2021 में भाग लेने के लिए भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं – OECD
- यूएई और सऊदी अरब द्वारा लॉन्च की गई साझा डिजिटल करेंसी का नाम है–अबेर (Aber)
- हाल ही में सीरिया और ईरान ने जितने समझौतों और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं–11
- वह देश जिसके नाविक ज़ॉन–लूक वैन डेन हीड ने 29 जनवरी 2019 को 212 दिन में बिना किसी अत्याधुनिक उपकरण की मदद से अकेले अपनी यॉट के ज़रिए समुद्र के रास्ते दुनिया का चक्कर लगाने की रेस जीत ली– फ्रांस
- केंद्र सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों के लिए सहायता के तौर पर जिस राज्य को अब तक का सबसे बड़ा 4714.28 करोड़ रुपये का पैकेज दिया है– महाराष्ट्र
- जिस आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष पी. सी. मोहनन और सदस्य जे.वी. मीनाक्षी ने अपने–अपने पद से इस्तीफा दे दिया है– राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग
- भारत में कैद में रखे हाथियों के पहले सर्वे के अनुसार, देश में कुल जितने हाथी कैद में हैं–2,454
- वह स्थान जहां 'नमक सत्याग्रह स्मारक' बनाया गया है–दांडी
- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित स्वस्थ भारत यात्रा के तहत जिस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया–तमिलनाडु
- वह देश जहां की डार्लिंग नदी में सूखे के कारण हज़ारों मछलियां मरी हुई पाई गईं–ऑस्ट्रेलिया
- हिंदी भाषा के लिए इन्हें हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया–चित्रा मुद्गल
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेस–वे बनाए जाने की घोषणा की गई। इस एक्सप्रेस–वे का नाम रखा गया है–गंगा एक्सप्रेस–वे
- वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसने इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला शटलर बन गईं– साइना नेहवाल
- नासा के अनुसार, जनवरी 2004 में लैंड करने वाले उसके ऑपरच्यूनिटी रोवर यान ने मंगल ग्रह पर जितने साल पूरे कर लिए हैं–15 साल
- रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि शारीरिक रूप से अक्षम पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को प्रति माह कम–से–कम जितने हजार रुपये पेंशन दी जाएगी–18 हजार
- राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के आंकड़ों के मुताबिक, हाईकोर्ट के प्रत्येक जज के पास जितने केस लंबित हैं–4,419
- आईसीसी ने पाकिस्तानी कप्तान सरफराज़ अहमद को नस्लवाद विरोधी कोड तोड़ने का दोषी मानते हुए उन पर जितने मैचों का बैन लगाया है–04
- इन्होने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 में पुरुष एकल वर्ग का ख़िताब जीता–नोवाक जोकोविच
- पहली जापानी महिला टेनिस खिलाड़ी का नाम जिसने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का ख़िताब जीता –नाओमी ओसाका
- वह राज्य जहां प्रधानमन्त्री मोदी ने हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की एकीकृत रिफाइनरी विस्तार परियोजना राष्ट्र को समर्पित की–केरल
- इन्हें वर्ष 2019 में भारत रत्न के लिए चयनित किया गया – नानाजी देशमुख, भूपेन हज़ारिका और प्रणब मुखर्जी
- 'ट्रेन–18' का नाम बदलकर रखे जाने की घोषणा की गई है – वंदे भारत एक्सप्रेस
- इंग्लैंड के खिलाफ एंटीगुआ टेस्ट में धीमी गति से ओवर फेंकने को लेकर आईसीसी ने मेज़बान विंडीज़ के कप्तान जेसन होल्डर पर जितने टेस्ट का बैन लगाया है– एक टेस्ट
- नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 के विरोध में जिस मणिपुरी फिल्मकार ने अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया है– अरिबम श्याम शर्मा
- आईसीसी की ताज़ा महिला वनडे बल्लेबाज़ी रैंकिंग में 3 स्थान की छलांग लगाकर जिस भारतीय ओपनर ने पहला स्थान हासिल कर लिया है– स्मृति मंधाना
- उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्ज़ियोयेव के आदेश पर देश में जिस विषय को पढ़ाने पर लगा बैन हटा लिया गया है– राजनीति शास्त्र
- विश्व कैंसर दिवस जिस दिन मनाया जाता है–04 फरवरी
- वह महिला क्रिकेटर जो 100 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेलने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर बनीं हैं–सना मीर
- देश के 22वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना हरियाणा में इस स्थान पर की जाएगी –रेवाड़ी
- सरकार द्वारा इन्हें हाल ही में सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है–ऋषि कुमार शुक्ला
- वह स्थान जहां प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में 3000–4000 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित, लगभग 335 किमी लंबी इस ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया–लद्दाख
- अमेरिका और रूस ने हाल ही में जिस परमाणु संधि से स्वयं को अलग कर के संधि को स्थगित करने की घोषणा की है –INF
- आंध्र प्रदेश में किस स्थान पर न्यायायिक परिसर का उद्घाटन किया गया है–अमरावती में
- विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है–
- 4 फरवरी
- अमेरिका में जिस महिला ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों में भाग लेने की घोषणा हाल ही में की

– तुलसी गब्बार्ड ने

हिमाचल प्रदेश समसामयिक

- हिमाचल प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री से नवाजा गया है–3

डॉक्टर ओमेश भारती– रेबीज की खोज के लिए, कांगड़ा

डॉक्टार जगत राम– नेत्र रोग विशेषज्ञ सिरमौर

अजय ठाकुर – एशिया कप में गोल्ड मेडल दिलाने के लिए, सोलन

- हिमाचल प्रदेश सरकार हिम गौरी के नाम से किस उत्पाद को मार्केट में उतारेगी –गाय के दूध को
- हिमाचली खिलाड़ी ज्योतिका दत्ता किस खेल से संबंधित है– तलवारबाजी
- रेड लव क्या है– स्विजरलैंड से मंगवाई गई सेब की किस्म
- पीजीआई चंडीगढ़ के निदेशक कौन है– जगतराम हिमाचल के सिरमौर जिले से
- राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर प्रस्तुत की गई–भाषा एवं संस्कृति व उद्योग विभाग की झांकी को कौन सा पुरस्कार मिला– प्रथम पुरस्कार
- वर्ष 2014 से लेकर 2017 तक हिमाचल प्रदेश में किस देश के सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटकों की आवाजाही दर्ज की गई– ब्रिटेन
- हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर खोला जाना है– बिलासपुर
- टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहां पर है– हमीरपुर में
- पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडीकल कॉलेज कहां पर है– चंबा
- हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंडी के शोधकर्ताओं ने किस वायरस की दवा खोजने में उल्लेखनीय प्रगति की है– जीका वायरस, इसका वाहक मच्छर होता है यह फ्लेवीवायरस जीन से संबद्ध पेथोजेन है।
- राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन है– रमेश धवाला
- मार्च 2019 में एचपी बोर्ड धर्मशाला की परीक्षा में कितने महिला परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं–45
- विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति और अनुमोदन के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है– हिम प्रगति
- प्रदेश में सरकारी स्कूलों में प्रि नर्सरी परीक्षाएं कब शुरू की गई हैं–अक्तूबर 2018
- हिमाचल प्रदेश तकनीकि विश्वविद्यालय हमीरपुर को कब शुरू किया गया था– वर्ष 2011
- हिम गौरी उत्पाद का संबंध किससे से है– गाय के दूध से
- बीती बरसात में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने कितने करोड़ रूपये जारी किए– 31744 करोड़ रूपये
- देश के प्रथम परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा का का संबंध हिमाचल के किस जिले से है– कांगड़ा के पालमपुर से
- सरदारा वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है– मंडी
- मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा किन निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किन दो स्थानों पर रोड शो आयोजित किए गए –बंगलुरू व हैदराबाद
- हिमाचल गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे विरेंद्र कंवर, पशुपालन मंत्री
- हिमाचल में बंपर सेब की फसल के लिए चिंलिंग आवर्स की आवश्कता होती है– 1400
- हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है– डाक्टर सुरेश सोनी
- सीनियर अल्पाइन स्नोबोर्डिंग चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई– मनाली के सोलंग में
- भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य के रूप में किस हिमाचली को सदस्य बनाया गया है– बिलासपुर के डाक्टर लेहरू राम सांख्यान
- ओडिशा ट्राइबल उत्सव में हिमाचल के किस जिले के सांस्कृतिक दल ने प्रस्तुति दी–लाहुल स्पीति
- हिमाचल के किस चिकित्सक को अमेरिका में बेस्ट ऑफ बेस्ट खिताब से नवाजा गया – डाक्टर जगतराम को
- सोलंगनाला में आयोजित राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता में किसने गोल्ड जीता – हिमाचल की संध्या ने
- पीएम मोदी ने किस स्थान पर हिमाचल के पहले आदर्श कालेज का ऑनलाइन उद्घाटन किया– चंबा के भरमौर में स्थित लील्ह कोठी में
- प्रदेश में कहां पर दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र का निर्माण कहां हो रहा है–ऊना स्थित चंद्रलोक कॉलोनी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जानिए किन किसानों को, कब से और कितनी रकम बैंक अकाउंट में आएगी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का एलान किया है। इसके तहत किसानों को 6 हजार रुपए सालाना मिलेंगे। द रीव टाइम्स के इस अंक में हम आपको बता रहे हैं कि जानिए इसकी पात्रता क्या होगी।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 फरवरी को अपने कार्यकाल का आखिरी और अंतरिम बजट पेश कर दिया है। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए देश के मध्यम वर्ग के लोगों से लेकर किसानों महिलाओं और व्यापारियों के लिए कई राहतभरी घोषणाएं की है। इस बजट में किसानों का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया गया है। किसान कल्याण के लिए 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि बीते वित्त वर्ष में किसानों से होने वाली आमदनी कम देखी गई, इसलिए देश में निर्धन भू–स्वामी किसान परिवारों को संरक्षित आय सहायता मुहैया कराने की आवश्यकता है जैसे बीज, उर्वरक, उपकरण, श्रम आदि खरीदने में उनकी मदद करना। ऐसा करके उन्हें साहूकारों के चंगुल में फंसने से बचाया जा सकता है।

किसानों के लिए पीएम किसान योजना

कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को 2019–20 का बजट पेश करते हुए 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (प्रधानमंत्री किसान योजना) की घोषणा की। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए इतिहास में पहली बार, सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से कम से कम 50 फीसदी अधिक निर्धारित किया है।

किस तरह मिलेगा योजना का लाभ

इसके अंतर्गत 2 हेक्टेयर जमीन के मालिक किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपए की दर से आय सहायता दी जाएगी। यह 2000 रुपए की तीन बराबर किस्तों में किसानों के बैंक खाते में दी जाएगी। इसका लाभ 12 करोड़ ऐसे किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है।

कब से मिलेगा इस योजना का लाभ

इस कार्यक्रम की पहली किस्त का भुगतान 31 मार्च 2019 तक कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम से सालाना 75,000 करोड़ का व्यय होगा। इस योजना से ना केवल उन्हें निश्चित आय मिलेगी बल्कि फसल कटाई और मौसमी आपदा के समय आकस्मिक जरूरतों में भी मदद करेगी।

12 करोड़ किसानों को मिलेगा फायदा

इस योजना से सीधे–सीधे देश के 12 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। योजना 1 दिसंबर 2018 से ही लागू होगी। और बताया गया कि 2 हजार रुपए की पहली किस्त जल्द ही किसानों की लिस्ट बनाकर उनके खातों में डाल दी जाएगी।

किसानों के लिए बजट में घोषणा करते हुए पीयूष गोयल ने कहा "हमारे मेहनती किसानों को फसलों का पूरा मूल्य नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए इतिहास में पहली बार सभी 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक निर्धारित किया है। देश के मेहनती किसानों ने पिछले साढ़े चार साल में रिकॉर्ड खाद्यान्न पैदा किया है। किसानों को व्यवस्थित इनकम सपोर्ट देने की जरूरत है। छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी सुनिश्चित कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ऐतिहासिक योजना हमने मंजूर की है।

योजना की मुख्य बातें

सरकार ने फसलों का एमएसपी लागत डेढ़ गुना करने की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मंजूरी के अंतर्गत 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसान को हर साल 6 हजार रुपये मिलेंगे।

किसानों के खाते में 3 किस्तों में पैसे जाएंगे।

इसका फायदा देश के 12 करोड़ किसानों को मिलेगा।

1 दिसंबर 2018 से यह योजना पूरे देश में लागू होगी।

किसान निधि के लिए 75,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य है।

पहली किस्त अगले महीने की 31 तारीख तक किसानों के खातों में डाल दी जाएगी।

आम बजट से हिमाचल के 8.45 लाख छोटे किसानों को होगा फायदा

हिमाचल कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में दो हेक्टेयर से कम काश्त वाले 8.45 लाख किसान जबकि कुल किसानों की संख्या 9.68

लाख तक है। प्रदेश में छोटी काश्त हैं। प्रदेश में किसानों और बागवानों की संख्या प्रदेश की कुल आबादी का अस्सी फीसदी तक है।

इनमें से करीब नब्बे फीसदी किसान और बागवान दो हेक्टेयर से कम की काश्त वाले हैं। हिमाचल प्रदेश फल एवं सब्जी उत्पादक संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी कृषि– बागवानी फसलों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। देश के किसानों की सिर्फ 22 फसलों को समर्थन मूल्य देने से कृषि फसलें उगाने का ज्यादा लाभ नहीं होगा।

कृषि ऋण भी माफ किया जाना चाहिए

देश के किसानों का कृषि ऋण भी माफ किया जाना चाहिए। छह हजार वार्षिक समर्थन आय काफी कम है परंतु सरकार ने यह शुरुआत करके अच्छा कदम उठाया है। इस राशि को बढ़ाकर कम से कम 18 हजार प्रति माह किया जाना चाहिए।

तभी जाकर किसानों और बागवानों को वित्तीय न्याय मिल सकेगा। हरीश चौहान कहते हैं कि वर्तमान में किसानों की 22 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है जबकि किसान कई तरह की दालें, तिलहन, सब्जियां और फल उगाते हैं। वर्तमान में गेहूं, धान, कपास, गन्ना, मूंग, उड़द तिलहनों सरसों, सोयाबीन सेब, आम, किन्नू, माल्टा और गलगल का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। जो किसान अन्य फसलों, फलों और सब्जियों की पैदावार करते हैं, उनके लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री किसान योजना: दूसरी किस्त पाने हेतु आधार अनिवार्य

केंद्र सरकार ने छोटे किसानों को नकद समर्थन उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री किसान योजना (PM Kisan scheme) के तहत पहली किस्त के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि, दूसरी किस्त पाने के लिए आधार को अनिवार्य किया गया है। सरकार ने बजट 2019 में किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना की शुरुआत की है.

पहली किस्त हेतु आधार अनिवार्य नहीं

आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार 2,000 रुपये की पहली किस्त के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन दूसरी किस्त पाने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य किया गया है। किसानों को अपनी पहचान बताने के लिए आधार नंबर देना होगा।

केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का क्रियान्वयन इसी साल से होगा और किसानों को पहली किस्त मार्च तक हस्तांतरित की जाएगी।

कृषि मंत्रालय के निर्देश:

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों को कहा है कि दिसंबर 2018 से मार्च 2019 की अवधि की किस्त पाने के लिये आधार नंबर जहां उपलब्ध होगा, वहीं लिया जाएगा। यदि आधार नंबर नहीं है तो अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों जैसे– ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा रोजगार कार्ड या केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी किसी अन्य पहचान पत्र के आधार पर पहली किस्त दी जा सकती है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि दूसरी और उसके बाद की किस्त पाने हेतु आधार नंबर अनिवार्य होगा।

स्टार्ट–अप इंडिया

भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नये विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी Startup India का निर्माण करना है जिससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हों। स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया है, की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2015 के भाषण में की गयी थी। ये मोदी सरकार द्वारा देश के युवाओं की मदद करने के लिये एक प्रभावी योजना है। ये पहल युवाओं को उद्योगपति और उद्यमी बनने का अवसर प्रदान करने के लिये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गयी है जिसके लिये एक स्टार्ट–अप नेटवर्क को स्थापित करने की आवश्यकता है। स्टार्ट–अप का अर्थ, देश के युवाओं को बैंको के माध्यम से वित्त प्रदान करना जिससे उनकी शुरुआत बेहतर मजबूती के साथ हो ताकि वो भारत में अधिक रोजगार सृजन कर सके ।

स्टार्ट–अप एक्शन प्लान का संक्षेपण

स्टार्ट–अप योजना को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इसका एक्शन प्लान या कार्ययोजना को दर्शाया है जो कि के उद्देश्य स्टार्ट–अप योजना के सभी पहलुओं को समाहित करता है। सरकार द्वारा इस संबंध में घोषित कार्य योजना स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के सभी पहलुओं को संबोधित करने और इस आंदोलन के प्रसार में तेजी लाने की उम्मीद करती है।

स्टार्ट–अप एक्शन प्लान मुख्य रुप से इन तीन बृहद भागों में विभाजित है:

- सरलीकरण और प्रारंभिक सहायता
- समर्थन और प्रोत्साहन अनुदान
- उद्योग–शैक्षिक जगत(एकेडेमिया) भागीदारी और उद्भवन

स्टार्टअप की परिभाषा (केवल सरकारी योजनाओं के लिए)

स्टार्टअप एक इकाई है, जो भारत में पांच साल से अधिक से पंजीकृत नहीं है और जिसका सालाना कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। यह एक इकाई है जो प्रौद्योगिकी या बौद्धिक सम्पदा से प्रेरित नये उत्पादों या सेवाओं के नवाचार, विकास, प्रविस्तारण या व्यवसायीकरण की दिशा में काम करती है।

इकाई पहले से अस्तित्व में व्यापार के विखंडन –पुनर्निर्माण द्वारा गठित नहीं की गई हो।

इकाई एक स्टार्टअप के तौर पर नहीं मानी जाएगी यदि पिछले वित्तिय वर्ष में उसका कारोबार 25 करोड़ रुपये से अधिक हो या उसने गठन की तिथि से 5 वर्ष पूरा कर लिया हो।

स्टार्टअप अंतर मंत्रालयी बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद कर लाभ के लिए योग्य होगा।

- स्टार्ट–अप एक्शन प्लान
- सरलीकरण और प्रारंभिक सहायता
- स्व–प्रमाणन पर आधारित अनुपालन व्यवस्था

इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स पर नियामक का बोझ कम करना है ताकि वे अपने मुख्य कारोबार पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अनुपालन की लागत कम रख सकें। नियामक व्यवस्थायें इस प्रकार और सरल एवं लचीली होंगी तथा निरीक्षण और अधिक सार्थक एवं सरल होगा।

स्टार्टअप इंडिया हब

पूरे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक संपर्क स्थान का निर्माण जिससे ज्ञान का आदान–प्रदान एवं वित्त पोषण हो सकें। सरकार मुख्य हित धारक होगी एवं केंद्र तथा राज्य सरकारों, भारतीय और विदेशी पूंजीपतियों, एंजेल नेटवर्क, बैंकों, इन्क्यूबेटरों, कानूनी भागीदारों, सलाहकारों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगी।

मोबाइल एप्लिकेशन और पोर्टल का रॉल आउट करना

सरकार और नियामक संस्थानों के साथ स्टार्टअप्स के लिए एक इंटरैक्टिव मंच के रूप में कार्य करेगा। 1 अप्रैल, 2016 से यह सभी प्रमुख मोबाइल ६ स्मार्ट डिवाइस प्लेटफार्मों पर उपलब्ध कराया जाएगा।

कानूनी सहायता और कम दर पर पर तेजी से पेटेंट परीक्षण

बौद्धिक संपदा अधिकार को बढ़ावा देने और जागरूकता लाने एवं नये स्टार्टअप्स के सतत विकास और तरक्की को सुनिश्चित करने के लिए, यह योजना पेटेंट दाखिल करने के कार्य को आसान कर देगा ।

स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक खरीद के शिथिलीकृत मानदंड

इसका उद्देश्य अनुभवी कंपनियों की तुलना में स्टार्टअप्स के लिए समान अवसर प्रदान करना है। सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा जारी निविदाओं के मामले में गुणवत्ता मानकों में छूट के बिना स्टार्टअप्स को 'पूर्वानुभव–टर्नओवर' के मानदंडों में छूट दी जाएगी ।

स्टार्टअप्स के लिए त्वरित निकासी

यह कार्य योजना स्टार्टअप्स के लिए असफलता की स्थिति में संचालन को बंद करने में आसानी प्रदान करेगा। स्टार्टअप्स के लिए एक इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल प्रदान किया जाएगा जो छह महीने के समय में लेनदारों के भुगतान के लिए कंपनी की आस्तियों को बेचने का प्रभारी होगा। यह प्रक्रिया सीमित देयता की अवधारणा को स्वीकार करेगी ।

समर्थन और प्रोत्साहन अनुदान

- स्टार्टअप्स के लिए धन की व्यवस्था

सरकार प्रति वर्ष 2500 करोड़ रुपये की एक प्रारंभिक निधि और 4 साल की अवधि में कुल 10,000 करोड़ रुपये की निधि की स्थापना करेगी।

स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी

स्टार्टअप्स के लिए वेंचर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों और अन्य उधारदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी (NCGTC) के माध्यम से क्रेडिट गारंटी तंत्र – सिडबी द्वारा प्रति वर्ष 500 करोड़ के बजट का प्रावधान अगले चार साल के लिए करने का विचार किया जा रहा है।

कैपिटल गेन पर कर में छूट

स्टार्टअप्स में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार उनको कैपिटल गेन में छूट देगी जिनको वर्ष के दौरान पूंजीगत लाभ हुआ है और जिन्होंनें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फंड ऑफ फंड्स में इस तरह के पूंजीगत लाभ का निवेश किया है ।

स्टार्टअप्स को तीन वर्ष के लिए टैक्स छूट

भारत में स्टार्टअप्स की कार्यशील पूंजी आवश्यकता को संबोधित करने, विकास को प्रोत्साहित करने और उन्हें एक प्रतियोगी मंच प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स के मुनाफे को 3 वर्ष की अवधि के लिए कर से मुक्त रखा जाएगा।

उचित बाजार मूल्य पर निवेश में टैक्स छूट

- स्टार्टअप्स में इन्क्यूबेटरों द्वारा निवेश पर निवेश कर से मुक्त रखा जाएगा ।

उद्योग– शिक्षा जगत(एकेडेमिया) भागीदारी और उद्भवन

अभिनव नई खोज के प्रदर्शन एवं सहयोग मंच प्रदान करने के लिए

स्टार्टअप उत्सवों का आयोजन –

भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार नें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप उत्सव शुरू करने का प्रस्ताव किया है। यह संभावित निवेशकों, परामर्शदाताओं और साथी स्टार्टअप्स को सम्मिलित करते हुए एक व्यापक जन समुदाय के समक्ष उनके काम और विचारों का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच होगा।

- अटल अभिनव मिशन (एआईएम) का स्व रोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) प्रोग्राम के साथ लॉन्च –

यह विशेष रूप से प्रौद्योगिकी संचालित क्षेत्रों में विश्व स्तर के नवाचार हब, भव्य चुनौतियां, स्टार्टअप कारोबार और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा।

- इनक्यूबेटर सेटअप के लिए निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का उपयोग

सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी में देश भर में इन्क्यूबेटरों की स्थापना के लिए एक नीति और ढांचे का निर्माण करेगा।

- राष्ट्रीय संस्थानों में अभिनव केंद्रों की स्थापना

देश में अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों में वृद्धि के लिए सरकार राष्ट्रीय संस्थानों में नवाचार और उद्यमिता के 31 केन्द्रों की स्थापना करेगी। छात्रों द्वारा स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए 13 केन्द्रों को 50 लाख रुपये की वार्षिक वित्त सहायता 3 साल के लिए प्रदान की जायेगी।

आई आई टी मद्रास में स्थापित अनुसंधान पार्क की तर्ज पर 7 नये अनुसंधान पार्कों की स्थापना –

शिक्षाविदों और उद्योग के संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों के माध्यम से सफल नवाचारों का विकास करने के लिए सरकार 100 करोड़ रुपये प्रति संस्थान के आरंभिक निवेश के साथ संस्थानों में 7 नए अनुसंधान पार्क की स्थापना करेगी । ये अनुसंधान पार्क आई आई टी मद्रास में स्थापित अनुसंधान पार्क की तर्ज पर होंगे।

जैव प्रौद्योगिकी सेक्टर में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना

भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र एक मजबूत विकास के पथ पर है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग वर्ष 2020 तक 2000 स्टार्टअप्स की स्थापना करने के लिए प्रति वर्ष करीब 300–500 नये स्टार्टअप्स की स्थापना के लिए प्रयासरत है।

छात्रों के लिए अभिनव केंद्रित कार्यक्रमों की शुरुआत

सरकार युवा छात्रों के बीच अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगी और इसके लिए कार्यक्रमों जैसे अभिनव कोर, निधि (एक भव्य चुनौती कार्यक्रम), उच्चतर आविष्कार योजना आदि की शुरुआत की है। शुरुआत में ये योजनायें केवल आईआईटी के लिए लागू होंगी और प्रत्येक परियोजना 5 करोड़ रुपये तक की हो सकती है।

वार्षिक इनक्यूबेटर ग्रैंड चैलेंज

इन्क्यूबेटर्स एक प्रभावी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए प्रारंभिक चरण में स्टार्टअप्स की पहचान करने और उन्हें अपने जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार पहले चरण में विश्व स्तर के इन्क्यूबेटरों के निर्माण की दिशा में निवेश करने का प्रस्ताव कर रही है। शुरुआती लक्ष्य ऐसे 10 इन्क्यूबेटरों की स्थापना करना है। इसके लिए सरकार विश्व स्तरीय बनने के लायक 10 संभावित इन्क्यूबेटरों की पहचान करेगी । इनमें से प्रत्येक को वित्तीय सहायता के रूप में 10 करोड़ रुपये दिये जायेंगे और ये इस तरह के अन्य

स्टैंड अप इंडिया
करें प्रयास पाएं विकास

इन्क्यूबेटरों के लिए संदर्भ मॉडल बनेंगे। इसके बाद इनको स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसे इन्क्यूबेटरों की पहचान के लिए ग्रैंड चैलेंज प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी और इसे वार्षिक रुप से जारी रखा जाएगा ।

योजना की प्रमुख बातें

- स्टार्टअप कारोबारियों द्वारा कमाये जाने वाले मुनाफे पर व्यावसाय शुरू होने के पहले तीन साल तक इनकम टैक्स से छूट होगी।
- ऐसे उद्यमों में वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों द्वारा किए गए निवेश के बाद अपनी संपत्ति बेचने पर 20 प्रतिशत की दर से लगने वाले पूंजीगत लाभ टैक्स से भी छूट होगी । यह छूट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उद्यम पूंजीकोषों के निवेश पर भी उपलब्ध होगी ।
- सरकार का 'स्टार्ट अप इंडिया' कार्यक्रम देश में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना है ताकि आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके और देश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मुहैया कराए जा सकें।
- सरकार की ओर से एक राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्ट कंपनी बनाने का प्रस्ताव है जिसमें अगले चार साल तक सालाना 500 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया जाएगा ।
- देश में नर्वप्रवर्तन सोच के साथ आने वाले तकनीक आधारित इन नये उद्यमों के लिये एक उदार पेटेंट व्यवस्था भी लाई जाएगी । पेटेंट पंजीकरण में इन उद्यमों को पंजीकरण शुल्क में 80 प्रतिशत छूट दी जायेगी।
- प्रधानमंत्री के अनुसार दिवाला कानून में स्टार्ट अप उद्यमों को कारोबार बंद करने के लिए सरल निर्गम विकल्प देने का प्रावधान भी किया जायेगा। इसके तहत 90 दिन की अवधि में ही स्टार्ट अप अपना कारोबार बंद कर सकेंगे ।
- छात्रों के लिए इनोवेशन के कोर्स शुरू किये जायेंगे और 5 लाख विद्यालयों में 10 लाख बच्चों पे फोकस करके इसको बढ़ाया जायेगा ।
- प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वःप्रमाणन आधारित अनुपालन व्यवस्था से स्टार्टअप पर नियामकीय बोझ कम होगा । स्वःप्रमाणन अनुपालन की यह व्यवस्था कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान, ठेका कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि कोष, पानी और वायु प्रदूषण कानूनों के मामले में उपलब्ध होगी ।
- स्टार्टअप को वित्तपोषण का समर्थन देने के लिये सरकार 2,500 करोड़ रुपये का शुरुआती कोष बनाएगी जिसमें अगले 4 साल के दौरान कुल 10,000 करोड़ रूपये का कोष होगा।
- दुनियाभर में स्टार्टअप की तीसरी बड़ी संख्या भारत में है। सरकार इन उद्यमों को सरकारी खरीद ठेके लेने के मामले में भी मानदंड में कई तरह की छूट देगी। स्टार्ट अप उद्यमों को सरकारी ठेकों में अनुभव और कारोबार सीमा के मामले में छूट दी जायेगी ।

इसमें महिलाओ के लिए विशेष व्यवस्था की गयी है ।

HP/129/SML/2019-2021

Advertorial

HPKVN

Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

N·S·D·C
National Skill Development Corporation
Transforming the skill landscape

PMKVY
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

कौशल विकास से आएगा निखार खुलेंगे रोज़गार के द्वार

भारत सरकार का उपक्रम

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

कौशल विकास प्रशिक्षण का सुनहरा मौका

आईआईआरडी और एचपीकेवीएन के संयुक्त तत्वाधान में

फार्मेसी एसिस्टेंट पाठ्यक्रम में पंजीकरण करवाएं, और अपने करियर को दे नई उड़ान

कार्य विवरण	पाठयक्रम की विशेषताएं
• दवाईयों की आपूर्ति का रख रखाव एवं प्रबंधन • मरीज का व्यक्तिगत प्रोफाईल तैयार करना जिसमें उसके उपचार और दवाईयो का पृष्ठत विवरण हो	• प्रशिक्षण फ्री, व्यावहारिक प्रशिक्षण • अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण

जूनियर साफ्टवेयर डेवेल्पर पाठ्यक्रम में पंजीकरण करवाएं, और अपने करियर को दे नई उड़ान

कार्य विवरण	पाठयक्रम की विशेषताएं
• सूचना तकनिकी उद्योग /आईटी में प्रारम्भिक स्तर पर सॉफटवेयर तैयार करना एवं उसका परीक्षण करना • कार्यालय में स्वच्छ, स्वस्थ एव सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना	• प्रशिक्षण फ्री, व्यावहारिक प्रशिक्षण • अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण

शैक्षणिक योग्यता

- आयुवर्ग - 18 से 35 वर्ष
- फार्मेसी एसिस्टेंट-न्यूनतम जमा दो (मेडीकल), कोर्स अवधि 4 महीने
- जूनियर साफ्टवेयर डेवेल्पर-न्यूनतम जमा दो, कोर्स अवधि 4 महीने
- अतिरिक्त लाभ-निःशुल्क बेसिक कंप्यूटर, साफ्ट स्किल और इंग्लिश लर्निंग

जूनियर सॉफ्टवेयर डेवेल्पर

मुख्य विशेषताएं

- निःशुल्क प्रशिक्षण
- निःशुल्क कोर्स पुस्तिका और किट
- 100 प्रतिशत सुनिश्चित रोज़गार
- केन्द्र सरकार की ओर से कौशल प्रमाण पत्र
- महिलाओं और दिव्यांगों को सरकार की ओर से वित्तीय लाभ

पहले आओ पहले पाओ
सीमित सीटें

फार्मेसी एसिस्टेंट

जरूरी दस्तावेज

- आधार कार्ड की प्रतिलिपि
- बैंक खाता प्रतिलिपि
- पांच पासपोर्ट साइज प्रतिलिपि
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र

* नियम और शर्तें लागू

प्रशिक्षण पूरा करने पर अभ्यर्थी को अपना व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए कम ब्याज दरों पर बिना गारन्टी के मुद्रा लोन दिलवाने की भी व्यवस्था है

कौशल हिमाचल समृद्ध हिमाचल

ज़िंदगी जियें-नशे को नहीं
स्वस्थ एवं नशामुक्त हिमाचल बनाने में दें सहयोग

IIRD
हम जानते हैं गाँव को बेहतर
Institute for Integrated Rural Development

IIRD Complex, Bypass Road, Shanan, Sanjauli, Shimla, H.P.-171006
Phone No. : 0177 2640761, Mob. 91311 24634, 85280 89637
Email : info@missionriev.in, Web : www.missionriev.in

RURALIZING INDIA-EMPOWERING VILLAGE RIEV
कि दुनिया देखती रह जाए